वर्ष : 34 | अंक : 351 | मुंबई, शुक्रवार, 27 फरवरी 2026 | RNI: MAHHIN/49994/91 | मूल्य : 3 रुपए | epaper.dobajedopahar.com | संपादक : अरुण लाल | संरक्षक : एन. के. पुरोहित

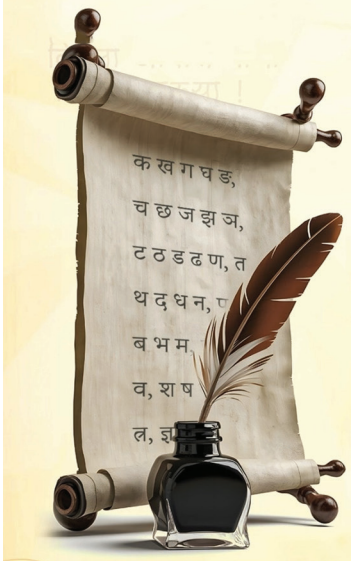

27 फरवरी

विश्व मराठी भाषा दिवस की शुभकामनाएं

DBD
दो बजे दोपहर

पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पांसिबिलिटी है

माझ्या मातीचे गायन
तुझ्या आकाश श्रुतींनी
जरा कानोसा देऊन कधी ऐकशील का रे
माझी धुळीतील चित्रे
तुझ्या प्रकाश नेत्रांनी
जरा पापणी खोलून कधी पाहशील का रे
माझ्या जहाजाचे पंख
मध्यरात्रीत माखले
तुझ्या किना *यास दिवा कधी लावशील का रे
माझा रांगडा अंधार
मेघामेघांत साचला
तुझ्या उषेच्या ओठांनी कधी टिपशील का रे - कवि कुसुमाग्रज

पवार परिवार का नया पावर सेंटर

- सुनेत्रा पवार बनीं एनसीपी अध्यक्ष, बारामती से लड़ेंगी उपचुनाव
- पार्थ पवार जाएंगे राज्यसभा
- विलय पर पूर्ण विराम, शरद पवार गुट ने भी बातचीत के दरवाजे बंद किए

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

वर्ली डोम में हुए एनसीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शक्ति प्रदर्शन के साथ सुनेत्रा पवार को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। प्रफुल्ल पटेल ने नाम का प्रस्ताव रखा और सुनील तटकरे ने उस पर मुहर लगाई। पार्टी के सभी छोटे-बड़े पदाधिकारियों ने हाथ उठाकर सुनेत्रा ताई के नेतृत्व पर अपना भरोसा जताया। फिलहाल प्रफुल्ल पटेल कार्यकारी अध्यक्ष और तटकरे प्रदेशाध्यक्ष की अपनी पुरानी भूमिकाओं में बने रहेंगे।

बारामती के 'गढ़' को बचाने की चुनौती

अजित पवार के निधन से बारामती की जो विधानसभा सीट खाली हुई है, वहां से अब सुनेत्रा पवार खुद उपचुनाव लड़ेंगी। दिलचस्प बात यह है कि शरद पवार गुट (NCP-SP) की सांसद सुप्रिया सुले ने भी संकेत दिए हैं कि सुनेत्रा पवार को सम्मान देते हुए उन्हें निर्विरोध विधायक चुना जा सकता है। इससे बारामती में एक बार फिर पवार परिवार का भावनात्मक और राजनीतिक दबदबा दिखने की उम्मीद है।

विलय की चर्चाओं का 'द एंड'

अजित दादा के जाने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों एनसीपी (AP और SP) फिर से एक हो सकती हैं, लेकिन अब इन संभावनाओं पर पूरी तरह से पानी फिर गया है। सुनील तटकरे ने शुरू से ही विलय से इनकार किया था, और अब शरद पवार गुट के शशिकांत शिंदे व जयंत पाटिल ने भी साफ कर दिया है कि अजित दादा के बिना अब विलय की बातचीत का कोई मतलब नहीं रह गया है। एनसीपी (SP) विधायक रोहित पवार ने एक भावुक खुलासा करते हुए कहा कि अजित दादा के निधन के बाद शरद पवार काफी दुखी थे। उन्होंने फोन पर बात करते हुए शरद पवार की आंखों में आंसू देखे थे। हालांकि, रोहित पवार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि शरद पवार की उम्र और मौजूदा हालात को देखते हुए वे अब पार्टी का विलय नहीं चाहते।

'पॉवर' का नया सेंटर: सुनेत्रा और पार्थ

सुनेत्रा पवार ने 31 जनवरी को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनने का इतिहास रचा था। अब वे पार्टी की अध्यक्ष भी हैं और विधायक दल की नेता भी। वहीं, उनके बेटे पार्थ पवार को राज्यसभा भेजने की तैयारी ने यह साफ कर दिया है कि अजित पवार का परिवार अब स्वतंत्र रूप से अपनी राजनीति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है।

खाकी का 'हाई-टेक' अवतार

- जीपीएस और आधुनिक तकनीक से लैस 1290 वाहन मुंबई पुलिस के बेड़े में शामिल
- हर थाने को मिलीं 10-10 नई गाड़ियां

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और अभेद्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार, 26 फरवरी 2026 को मुंबई पुलिस को 1290 नए वाहनों की सौगात दी। नरीमन पॉइंट पर आयोजित एक भव्य समारोह में इन आधुनिक गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस नए बेड़े में 633 चार पहिया वाहन (स्कॉर्पियो और अर्मेनिया) तथा 657 दुपहिया वाहन शामिल हैं। मुख्यमंत्री, जिनके पास गृह विभाग की भी जिम्मेदारी है, ने विश्वास जताया कि इन संसाधनों से मुंबई पुलिस की कार्यक्षमता अब वैश्विक स्तर की हो जाएगी।

रिस्पॉन्स टाइम पर 'लगाम' कसने की तैयारी

मुंबई पुलिस अभी किसी भी इमरजेंसी कॉल पर औसतन 5.30 मिनट में पहुँच जाती है, लेकिन अब इस समय को और भी कम करने का लक्ष्य है। ये नई गाड़ियाँ केवल चलने का साधन नहीं, बल्कि 'पहियों पर चलता कंट्रोल रूम' हैं।

हर थाने की हुई 'बल्ले-बल्ले'

मुंबई के सभी 90 पुलिस स्टेशनों की ताकत अब कई गुना बढ़ जाएगी। प्लान के मुताबिक, हर पुलिस स्टेशन के हिस्से में 10 नई गाड़ियाँ आएंगी। इसमें 5 टू-व्हीलर, 4 स्कॉर्पियो और 1 बड़ी अर्मेनिया गाड़ी शामिल है। यानी अब गली-मोहल्लों की गश्त हो या मुख्य सड़कों पर पीछा करना, पुलिस के पास संसाधनों की कोई 'कंगाली' नहीं रहेगी।

अपराधियों में खौफ

गृह विभाग की कमान संभाल रहे फडणवीस ने कहा कि इन गाड़ियों के आने से मुंबई पुलिस की रिस्पॉन्स क्षमता अब 'इंटरनेशनल लेवल' की हो जाएगी। जब सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी दिखेगी, तो आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस करेगी और बदमाशों के मन में कानून का डर बैठेगा। पुलिस कमिश्नर देवेन भारती ने भी इस नए जोश का स्वागत किया है।

ब्रीफ न्यूज़

6 साल में 30 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा

मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा जारी किया है। उन्होंने जानकारी दी है कि बीते 6 साल में महाराष्ट्र में 30 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा है। राज्य सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि पिछले छह वर्षों में राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साल 2020 से 2026 के बीच करीब 30 लाख लोगों को कुत्तों द्वारा काटने के मामले दर्ज किए गए, जबकि 2021 से 2023 की अवधि में 30 लोगों की कुत्तों द्वारा काटने से हुई रेबीज के चलते मौत हो गई है। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया है कि मुंबई, अहिल्यानगर, वसई-विरार, सांगली, भिवंडी, रायगड और जालना में आवारा कुत्तों की संख्या में अधिक वृद्धि देखी गई है। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि पर्यटन एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग की ओर से 5 जनवरी 2026 को एक शासनादेश जारी कर पर्यटन स्थलों और विभाग के परिसरों में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं को आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए विशेष रूप से कोई अलग फंड उपलब्ध नहीं कराया जा सकता।

स्त्री बीज तस्करी करने वाले आरोपियों पर लगे मकोका : वाघ

मुंबई। विधान परिषद में भाजपा विधायक चित्रा वाघ ने बदलापुर में स्त्री बीज (एग) तस्करी मामले के आरोपियों के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। गुरुवार को सदन में चित्रा ने कहा कि बदलापुर में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं का बीज निकालकर तस्करी की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों गिरफ्तार किया है। लेकिन इस मामले की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। आरोपियों के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। पीड़ित महिलाओं को कानूनी और आर्थिक मदद की जानी चाहिए। इसके साथ ही सरकार को राज्य की सभी आईवीएफ क्लीनिक का ऑडिट करना चाहिए।

अजित पवार विमान हादसा

सदन में 'सवालों का बवंडर'

- विधान परिषद सभापति ने सरकार को दिए तथ्य पेश करने के निर्देश
- सीबीआई जांच और एफआईआर की मांग

मुंबई। गुरुवार को महाराष्ट्र विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होते ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक शशिकांत शिंदे ने 28 जनवरी को हुए विमान हादसे का मुद्दा उठाकर सबको चौंका दिया। उन्होंने इस मामले पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया और साफ़ तौर पर कहा कि पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत की परिस्थितियां सामान्य नहीं लग रही हैं। अमोल मिटकरी और रोहित पवार जैसे नेताओं ने भी इस हादसे के पीछे 'गहरी साजिश' होने का शक जताया है।

खाकी पर बदसलूकी का इल्जाम

मामला तब और गरमा गया जब विधायक अमोल मितकारी ने मुंबई के एक पुलिस उपायुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मितकारी का आरोप है कि जब वे और रोहित पवार एफआईआर दर्ज कराने गए, तो उक्त अधिकारी ने न केवल शिकायत लेने से मना किया, बल्कि विधायकों के साथ 'दुर्व्यवहार' भी किया। उन्होंने सदन से मांग की कि ऐसे अधिकारियों पर तुरंत गाज गिरनी चाहिए जो जनप्रतिनिधियों की बात सुनने के बजाय कंपनी को बचाने में लगे हैं।

विमान कंपनी की 'लापरवाही' पर वार

शशिकांत शिंदे ने सदन में दावा किया कि नागर विमानन महानिदेशालय ने पहले ही 'वीएसआर वेंचर्स' (जिसका विमान बारामती में गिरा था) के चार विमानों को उड़ने से रोक दिया था क्योंकि वे सुरक्षा नियमों को ताक पर रख रहे थे। सवाल यह उठाया गया कि जब कंपनी पहले से ही सुरक्षा मानकों में 'फेल' थी, तो उसे उड़ने की इजाजत किसने दी और लापरवाही सामने आने के बाद भी अब तक प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई? विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया और पूछा कि क्या यह वाकई एक हादसा था या कोई 'भीतरघात' (Sabotage)?

सड़कों पर थमा मौत का तांडव

- जनवरी में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 8% की कमी

मुंबई। परिवहन विभाग द्वारा लागू की गई नई योजनाओं का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। जनवरी 2026 में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 8.05 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल जनवरी (2025) में जहां 1,427 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, इस साल यह आंकड़ा घटकर 1,312 रह गया है। कुल हादसों की संख्या में भी 2 प्रतिशत की कमी आई है, जो सुरक्षा की दिशा में एक बड़ी जीत है। सड़क सुरक्षा के कड़े उपायों का सबसे ज्यादा असर नंदुरबार में दिखा, जहां मृत्यु दर में 50 प्रतिशत की भारी कमी आई है। सोलापुर और वाशिम में 36%, सिंधुदुर्ग में 29% और वर्धा में 28% की गिरावट दर्ज की गई है। नांदेड़ और नागपुर जैसे शहरों में भी मौतों का ग्राफ 21% तक नीचे आया है। इन जिलों में प्रशासन की सख्ती और जनता की जागरूकता का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है।

> तकनीक और जागरूकता के मेल से हम सही रास्ते पर हैं। सरकार का लक्ष्य बहुत स्पष्ट है— वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों को आधा (50%) करना है। इसके लिए नई भर्तियों, सख्त नियमों और सड़कों की बनावट में सुधार पर लगातार काम किया जा रहा है ताकि हर मुसाफिर सुरक्षित अपने घर लौट सके।
> **-भरत कलसकर,** अपर परिवहन आयुक्त

'स्मार्ट' तकनीक से कम होगा खतरा

राज्य सरकार अब सड़कों को 'हाइ-टेक' बनाने जा रही है। लगभग 25 हजार किलोमीटर की सड़कों पर आधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली (ITMS) लगाई जाएगी।

सीबीआई ने अनिल अंबानी पर दर्ज किया केस

- 2200 करोड़ की धोखाधड़ी का है मामला

नई दिल्ली/मुंबई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उद्योगपति अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ 2,200 करोड़ से अधिक की कथित बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सीबीआई के प्रवक्ता के अनुसार, यह मामला वर्ष 2013 से 2017 के बीच बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ की गई धोखाधड़ी से जुड़ा है। मंगलवार को बैंक से औपचारिक शिकायत मिलने के बाद एजेंसी ने तुरंत कार्रवाई की और अनिल अंबानी के आवास तथा कंपनी के कार्यालयों पर छापेमारी की, जहाँ से लेनदेन से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

लोन डिफॉल्ट और बैंक को भारी वित्तीय नुकसान

बैंक ऑफ बड़ौदा ने आरोप लगाया है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस को दिए गए ऋण के कारण बैंक को 2,220 करोड़ से अधिक का भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। कंपनी की वित्तीय स्थिति बिगड़ने के कारण उनके खातों को वर्ष 2017 में ही 'नॉन-परफॉर्मिंग एसेट' (NPA) घोषित कर दिया गया था। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम और सीबीआई की एफआईआर पर रिलायंस कम्युनिकेशंस या अनिल अंबानी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

बॉम्बे हाईकोर्ट से स्टे हटने के बाद बढ़ी मुश्किलें

सीबीआई की यह कार्रवाई कानूनी अड़चनें दूर होने के बाद शुरू हुई है। दरअसल, अनिल अंबानी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खातों को 'फ्रॉड' घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक (स्टे) लगवा रखी थी। 23 फरवरी को अदालत द्वारा यह स्टे हटाए जाने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई।

राउत को राहत

मेधा सोमैया मानहानि केस: कोर्ट ने संजय राउत को किया बरी

मुंबई। संजय राउत के लिए यह मामला गले की हड्डी बन गया था, जब निचली मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें मानहानि का दोषी मानते हुए 15 दिन की जेल और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। हालांकि, ऊपरी अदालत (सत्र न्यायालय) ने गुरुवार को इस फैसले को पूरी तरह पलट दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि राउत पर लगाए गए आरोप टिकने योग्य नहीं हैं और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया।

यह पूरा विवाद मीरा-भायंदर नगर निगम में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण से जुड़ा था। संजय राउत ने आरोप लगाया था कि मेधा सोमैया और उनके पति ने इसमें करीब 100 करोड़ रुपये का घोटाला किया है। मेधा सोमैया का कहना था कि ये आरोप पूरी तरह झूठे हैं और उनकी सामाजिक छवि को खराब करने के लिए लगाए गए हैं। इसी आधार पर उन्होंने मानहानि का मुकदमा ठोका था।

राज्यसभा चुनाव | 7 सीटों के लिए सियासी बिसात बिछी

सियासी 'जंग' में कूदी कांग्रेस, ठोंका दावा

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों के लिए सियासी बिसात बिछ चुकी है, लेकिन महाविकास आघाड़ी (MVA) के लिए गणित काफी टेढ़ा है। शिवसेना (UBT), कांग्रेस और एनसीपी (SP) के पास कुल मिलाकर केवल 46 विधायक हैं, जो केवल एक उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने के लिए काफी हैं। अब मुसीबत यह है कि इस इकलौती सीट पर गठबंधन के तीनों बड़े खिलाड़ी अपनी दावेदारी जता रहे हैं, जिससे 'दोस्ती' में दरार के संकेत मिलने लगे हैं।

एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की ओर से मांग उठ रही है कि उनके सबसे बड़े नेता शरद पवार को ही वरिष्ठता के आधार पर दोबारा राज्यसभा भेजा जाए। वहीं, चर्चा है कि उद्धव गुट की ओर से आदित्य ठाकरे के नाम पर भी विचार चल रहा है। दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि उनका प्रतिनिधि दिल्ली की संसद में पहुंचे, लेकिन कांग्रेस की नई मांग ने इस रेस को और पेचीदा बना दिया है।

कांग्रेस का 'नेशनल पार्टी' वाला दांव

जब शरद पवार और शिवसेना के बीच खींचतान चल रही थी, तभी कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि यह सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए। उनका तर्क है कि चूंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए राज्यसभा में उसका प्रतिनिधित्व होना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि कांग्रेस इस सीट को लेकर अपनी दिलचस्पी दिखा चुकी है और इस पर अब तीनों पार्टियों को गंभीरता से विचार करना होगा।

विपक्षी एकजुटता की 'अग्निपरीक्षा'

यह चुनाव केवल राज्यसभा की एक सीट का नहीं है, बल्कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए महाविकास आघाड़ी की मजबूती का टेस्ट भी है। अगर तीनों दल एक नाम पर सहमत नहीं हुए, तो गठबंधन की एकता पर सवाल उठेंगे और इसका सीधा फायदा सत्ताधारी महायुति को मिल सकता है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या कांग्रेस अपना दावा छोड़ेगी या शरद पवार और उद्धव ठाकरे कोई नया 'फॉर्मूला' निकालेंगे।

न्यूज़ ब्रीफ

अस्पताल पर चला 'सरकारी डंडा'

कल्याण। कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका के नए आयुक्त अभिनव गोयल ने टैक्स वसूली को लेकर कड़ा रुख अपना लिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो लोग निगम का पैसा दबाकर बैठे हैं, उनसे अब नरमी से बात नहीं होगी। इसी कड़ी में प्रभाग 4/जे (प्रभाग क्षेत्र-जे) में टैक्स वसूली की मुहिम को तेज करते हुए एक बड़े डिफॉल्टर पर गाज गिराई गई है। मुरबाड रोड पर स्थित ए एंड जी हॉस्पिटल, जिसका संचालन भारत एम. सूचक द्वारा किया जा रहा है, निगम के निशाने पर आ गया। इस प्रॉपर्टी (मिलकियत क्र. B02012338601) पर एक या दो लाख नहीं, बल्कि पूरे 75,47,025 की टैक्स राशि बकाया है। लंबे समय से नोटिस देने के बावजूद जब बकाया नहीं चुकाया गया, तो निगम ने 'तालाबंदी' का रास्ता चुना। सहायक आयुक्त सविता हिले और उनकी टीम ने अस्पताल पहुँचकर यह कार्रवाई की। अस्पताल की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए फिलहाल उसके एडमिनिस्ट्रेटिव (प्रशासनिक) रूम को सील कर दिया गया है। टीम ने मौके पर पहुँचकर सरकारी मुहर लगा दी, जिससे यह संदेश गया है कि रसूख चाहे कितना भी बड़ा हो, टैक्स तो भरना ही पड़ेगा।

इतिहास सही होता तो औरंगजेब हीरो नहीं होता: मुख्यमंत्री

मुंबई। मुख्यमंत्री फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि अगर पिछले 70 सालों में भारत का इतिहास सही तरीके से पढ़ाया गया होता, तो आज कोई भी मुसलमान औरंगजेब को अपना आदर्श नहीं मानता। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले NCERT की किताबों में मुगलों के लिए 17 पेज होते थे और छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए सिर्फ एक। लेकिन अब पीएम मोदी के नेतृत्व में इसे बदला गया है और शिवाजी महाराज के इतिहास को 20 पेजों में विस्तार से जगह दी गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल द्वारा शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान की बराबरी करने वाले बयान पर फडणवीस ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ाई अपनी सत्ता बचाने के लिए लड़ी थी, जबकि शिवाजी महाराज का लक्ष्य 'स्वराज्य' और जन-कल्याण था। फडणवीस ने ऐतिहासिक आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि टीपू सुल्तान ने हजारों हिंदुओं और नायरों का कत्ल किया, इसलिए उनकी तुलना शिवाजी महाराज से करना अपमानजनक है।

स्मार्ट मीटर लगाने पर विवाद, कर्मचारी के साथ मारपीट

अंबरनाथ। अंबरनाथ के वन नाका क्षेत्र में एक बिजली उपभोक्ता द्वारा महावितरण के वरिष्ठ तकनीशियन रतिराम सपकाले पर हमला करने का गंभीर मामला सामने आया है। घटना उस समय हुई जब सपकाले बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए इलाके में गए थे। आरोपी उपभोक्ता, दत्तु जाधव, इस बात से नाराज था कि महावितरण ने उसकी बिना अनुमति के घर का पुराना मीटर हटाकर नया स्मार्ट मीटर क्यों लगाया। गुस्से में आकर जाधव ने कर्मचारी को अपशब्द कहे और उनके साथ हिंसक मारपीट की, जिससे रतिराम सपकाले घायल हो गए।

ट्रैफिक की 'चिक-चिक' होगी खत्म

स्कूलों के पास और मुख्य चौराहों पर पुलिस की तैनाती बढ़ेगी

अवैध रिक्शा स्टैंडों का होगा सफाया

डीबीडी संवाददाता । भाईंदर

शहर में रोज लगने वाले यातायात जाम से स्थानीय नागरिक लंबे समय से त्रस्त हैं। ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए महापौर डिंपल मेहता ने एमबीवीवी यातायात विभाग को अहम निर्देश दिए। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से मनपा मुख्यालय में महापौर डिंपल मेहता, उपमहापौर ध्रुवकिशोर पाटिल और एमबीवीवी यातायात विभाग (मीरा-भाईंदर यूनिट) के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सागर इंगोले के साथ संयुक्त बैठक हुई, जिसमें समस्या पर विस्तार से चर्चा की गई।

निजी बसों की पार्किंग बनी बड़ी समस्या

भाईंदर (प.) के नेताजी वीर सुभाषचंद्र बोस मैदान और मीरा रोड स्थित एल.आर. तिवारी इंजीनियरिंग महाविद्यालय के पास मुंबई और ठाणे की निजी बसों की पार्किंग का मामला कई बार तूल पकड़ चुका है। यातायात विभाग द्वारा दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। इस मुद्दे पर भी बैठक में गंभीरता से विचार-विमर्श किया गया।

संयुक्त और सुनियोजित प्रयास का भरोसा

महापौर डिंपल मेहता के अनुसार, शहर को जाम से राहत दिलाने के लिए संयुक्त रूप से लगातार और सुनियोजित प्रयास किए जाएंगे। नगर निगम ने मीरा रोड (पू.) के लतीफ पार्क, कनकिया परिसर और स्टार बाजार में पार्किंग की व्यवस्था की है। हालांकि, पर्याप्त जानकारी के अभाव में स्थानीय नागरिक इन पार्किंग स्थलों का समुचित उपयोग नहीं कर रहे हैं। यदि इनका व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाए तो सड़कों के किनारे वाहनों की पार्किंग कम होगी और ट्रैफिक जाम से राहत मिल सकेगी। महापौर के अनुसार, इस संबंध में यातायात विभाग को जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है।

स्कूलों के पास जाम का निकलेगा हल

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सागर इंगोले ने महापौर को आश्वस्त किया कि यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि कुछ स्कूलों के आसपास वाहन पार्किंग को लेकर अभिभावकों पर सीधे जुर्माना लगाना संभव नहीं है। ऐसे में संबंधित स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक कर समाधान निकाला जाएगा। शहर की मुख्य सड़कों और चौराहों पर अवैध पार्किंग तथा सड़कों पर संचालित अवैध गैराज भी जाम की बड़ी वजह हैं। महापौर ने ऐसे वाहन चालकों और गैराज संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

जाम, अवैध पार्किंग और बंद सिग्नलों पर फोकस

बैठक में महापौर डिंपल मेहता और उपमहापौर ध्रुवकिशोर पाटिल ने शहर के मुख्य मार्गों और आंतरिक सड़कों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक वार्डन की व्यवस्था, स्कूलों के पास लगने वाले जाम, बंद पड़े सिग्नल, अवैध रिक्शा स्टैंड, सड़कों पर अवैध पार्किंग और कुछ क्षेत्रों में ट्रैफिक पुलिस की तैनाती जैसे मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया। आवश्यक सुझाव देने के साथ कड़े कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए।

विट्ठलवाड़ी पुलिस का 'एंजल डांस बार' पर छापा

दस बार डांसर समेत दर्जनभर गिरफ्तार

डीबीडी संवाददाता । उल्हासनगर

उल्हासनगर के कैंप नंबर 4 स्थित श्रीराम चौक पर संचालित 'एंजल डांस बार' पर विट्ठलवाड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक कोली को सूचना मिली थी कि यह बार नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए पूरी रात खुला रहता है और यहाँ संदिग्ध अपराधियों की आवाजाही बनी रहती है। इस सूचना के आधार पर पुलिस की एक विशेष टीम ने मौके पर छापेमारी की, जहाँ अश्लील गानों और कम कपड़ों में युवतियों को ग्राहकों को लुभाने के लिए नचाया जा रहा था।

10 डांसरों सहित मैनेजर और वेटर गिरफ्तार

छापेमारी के दौरान पुलिस ने 10 बार डांसरों सहित कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में बार मैनेजर रफीकुल्ला हरेश शेख और दो वेटर, मिनल नासिक और दिनेश गौड़ा शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, ये सभी लोग मिलीभगत कर अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। यह बार लंबे समय से इलाके में विवादों और आपराधिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में चर्चा का विषय बना हुआ था।

अपराधियों के जमावड़े और अवैध बारों पर कड़ी नजर

पुलिस की इस कार्रवाई से उल्हासनगर के अवैध बार संचालकों में हड़कंप मच गया है। जाँच में यह भी सामने आया है कि इन बारों में बाहरी अपराधी सक्रिय रहते हैं, जिससे स्थानीय सुरक्षा के लिए खतरा बना रहता है। विट्ठलवाड़ी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इलाके में चल रहे अन्य 4-5 संदिग्ध बारों पर भी उनकी पैनी नजर है और आने वाले दिनों में इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनी रहे।

60 साल पुरानी बस्ती पर विस्थापन का खतरा

विधानसभा में गूंजा मामला

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

घोडबंदर रोड स्थित पातलीपाडा-डोंगरीपाडा क्षेत्र में पिछले 5-6 दशकों से बसी एक बड़ी आबादी आज अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। लगभग 60 साल पहले अस्तित्व में आई इस बस्ती में वर्तमान में 5,000 से अधिक घरों में करीब 15 से 20 हजार नागरिक निवास करते हैं। यहाँ के निवासी न केवल नियमित रूप से टैक्स भरते हैं, बल्कि उनके पास मतदाता पहचान पत्र और स्कूल, सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। हालांकि, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के आरोपों के चलते अब इन घरों पर प्रशासनिक कार्रवाई की तलवार लटक रही है।

नियमों के तहत नियमितीकरण की मांग

विधायक संजय केलकर ने गुरुवार को विधानसभा में 'पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन' के जरिए इस संवेदनशील मुद्दे को उठाया। उन्होंने सदन को बताया कि इन बस्तियों को केवल 'अतिक्रमण' मानकर तोड़ना न्यायोचित नहीं होगा। केलकर ने मांग की कि राज्य सरकार को इस मामले में तुरंत दखल देना चाहिए और 'सेक्शन 51' के नियमों के तहत इन निर्माणों को नियमित (Regularize) करने की संभावना तलाशनी चाहिए। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से अपील की कि हजारों नागरिकों को राहत देने के लिए सरकार को ठोस नीतिगत फैसला लेना चाहिए।

कोर्ट का आदेश और निवासियों की बढ़ती परेशानी

इस संकट की जड़ साल 2010 में दायर एक जनहित याचिका (PIL) है, जिसमें इस बस्ती को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बताया गया था। अदालत के आदेश के बाद जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा इन झोपड़ियों को तोड़ने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। बार-बार मिल रहे इन नोटिसों ने हजारों परिवारों की नींद उड़ा दी है। निवासियों का तर्क है कि वे दशकों से यहाँ रह रहे हैं और प्रशासन उन्हें अचानक बेघर नहीं कर सकता। इसी समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने विधायक संजय केलकर से हस्तक्षेप की गुहार लगाई थी।

डीजीएमसी और पीआरएसआई मुंबई के बीच एमओयू

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

मुंबई के मशहूर देवीप्रसाद गोएंका मैनेजमेंट कॉलेज (DGMC) और पब्लिक रिलेशन्स सोसायटी ऑफ इंडिया (PRSI) के बीच एक बड़ा समझौता (MoU) हुआ है। इस गठबंधन का असली मकसद छात्रों को किताबी कीड़ा बनाने के बजाय उन्हें जनसंपर्क की प्रोफेशनल दुनिया के लिए तैयार करना है। अब छात्रों को इंडस्ट्री के 'बड़ों' से सीधे मिलने और उनसे काम सीखने का मौका मिलेगा।

'नालंदा' मंच से होगा 'चमत्कार'

इस समझौते के तहत 'नालंदा' नाम का एक छात्र मंच बनाया गया है। इसके जरिए छात्रों को न केवल नामी कंपनियों में इंटर्नशिप मिलेगी, बल्कि उनके लिए वर्कशॉप, सेमिनार और एक्सपर्ट सेशन भी आयोजित किए जाएंगे। यानी अब छात्र क्लासरूम में बैठे-बैठे ही यह जान सकेंगे कि जनसंपर्क की दुनिया में असली 'मैजिक' कैसे होता है।

हवा के साथ बदलना होगा हुनर

पीआरएसआई की अध्यक्षा अनीता श्रीवास्तव ने कहा कि आज के बदलते रोज़गार बाज़ार में केवल डिग्री काफी नहीं है। इस पहल से छात्रों को एक ऐसा 'नेटवर्क' मिलेगा जहाँ वे अपनी स्किल को निखार सकेंगे। वहीं डॉ. अमी वोरा का मानना है कि यह समझौता शिक्षा और इंडस्ट्री के बीच की उस खाई को पाटने का काम करेगा, जो अक्सर छात्रों के करियर की राह में अड़चन बनती है।

भविष्य के 'मीडिया स्टार्स' के लिए तैयारी

DGMC, जो राजस्थानी सम्मेलन एजुकेशन ट्रस्ट का हिस्सा है, पहले से ही मास कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट जैसे मॉडर्न कोर्स के लिए जाना जाता है। अब पीआरएसआई जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के साथ जुड़ने से यहाँ के छात्रों को 'एथिकल वैल्यूज' (नैतिक मूल्यों) और प्रोफेशनल कुशलता का वो पाठ पढ़ने को मिलेगा, जो उन्हें एक जिम्मेदार मीडिया प्रोफेशनल बनाएगा।

दिग्गजों ने किया 'डील' पर साइन

इस अहम समझौते पर PRSI मुंबई की अध्यक्षा अनीता श्रीवास्तव और कॉलेज की प्राचार्या डॉ. अमी वोरा ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर मीडिया एक्सपर्ट्स और पीआर जगत के कई दिग्गज मौजूद थे। इस डील का सीधा असर कॉलेज के उन छात्रों पर पड़ेगा जो फिल्म, टेलीविजन, एनीमेशन और डेटा साइंस जैसे कोर्स कर रहे हैं और मीडिया में अपना भविष्य देख रहे हैं।

लापरवाह अफसरों की अब खैर नहीं

डिलीवरी के वक्त गायब रहने वाले डॉक्टर सस्पेंड, दो की छुट्टी

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

पालघर जिले के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) में प्रसव के दौरान डॉक्टरों की अनुपस्थिति की गंभीर घटना पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य राज्य मंत्री मेघना साकोरे-बोर्डिकर ने बताया कि इस मामले में संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और दो अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) डॉक्टरों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। सदस्य चित्रा वाघ और प्रवीण दरेकर द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने स्पष्ट किया कि सुरक्षित और संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

निरीक्षण और बायोमेट्रिक उपस्थिति से बढ़ेगी जवाबदेही

राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों और कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार के 'NAQOS' ऐप के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और ग्रामीण अस्पतालों का आठ अलग-अलग मानदंडों पर समय-समय पर निरीक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही, 'कायाकल्प' और लेबर रूम निरीक्षण कार्यक्रमों के तहत अस्पतालों में साफ-सफाई और गुणवत्ता के मानकों को सख्ती से लागू किया जा रहा है ताकि दूर-दराज के इलाकों में भी उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। पालघर जिले में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वर्तमान में जिले में चिकित्सा अधिकारियों के स्वीकृत 112 पदों में से 34 खाली हैं, जबकि PHC स्तर पर 87 में से केवल 8 पद रिक्त हैं, जिन्हें जल्द भरने का आश्वासन दिया गया है। राज्य मंत्री मेघना साकोरे-बोर्डिकर ने यह भी घोषणा की कि पालघर की पूरी स्वास्थ्य प्रणाली की विस्तृत समीक्षा के लिए जल्द ही एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी, जिससे नागरिकों को समय पर और बेहतर उपचार मिलना सुनिश्चित हो सके।

'सारथी' और 'बार्टी' की तर्ज पर अब 'मार्टी'

अल्पसंख्यक संस्था 'मार्टी' जल्द होगी सक्रिय

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री सुनेत्रा पवार ने विधानसभा में घोषणा की है कि अल्पसंख्यक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था (MARTI) जल्द ही नियमित कामकाज शुरू कर देगी। सपा विधायक रईस शेख के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि छत्रपति संभाजीनगर स्थित हज हाउस में संस्था का अस्थायी कार्यालय स्थापित कर दिया गया है। इसके संचालन के लिए 3.12 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है और कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए सलाहकार की नियुक्ति भी हो चुकी है।

कौशल विकास और नए आयुक्तालय की स्थापना

सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के कौशल संवर्धन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए छत्रपति संभाजीनगर में ही एक नया 'अल्पसंख्यक आयुक्तालय' शुरू किया है। सुनेत्रा पवार के अनुसार, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना और युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को जल्द पूरा कर धरातल पर काम शुरू किया जाए। दूसरी ओर, विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए वर्ष 2026 को रिक्रूटमेंट ईयर (भर्ती वर्ष) के रूप में मनाने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 1.53 लाख पदों में से 85,363 उम्मीदवारों की नियुक्तियां पूरी हो चुकी हैं। शिंदे ने आश्वासन दिया कि शेष 75,000 से अधिक रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी जून तक तेज कर दी जाएगी, जिससे महाराष्ट्र की विकास यात्रा को नई गति मिलेगी।

ठाणे को 'चकाचक' करने का मेगा प्लान

शिकायतों के बाद सफाई इंस्पेक्टर्स को लगी फटकार; पानी और दरवाजों की मरम्मत के निर्देश

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

ठाणे की मेयर शर्मिला पिंपलोलकर ने आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए घन कचरा विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मेयर ने निर्देश दिया कि शहर के सभी छोटे-बड़े नालों की सफाई का काम मार्च के अंत तक अनिवार्य रूप से शुरू हो जाना चाहिए, ताकि मई के अंत तक इसे पूरी तरह संपन्न किया जा सके। स्वर्गीय अरविंद पेंडसे हॉल में हुई इस बैठक में डिप्टी कमिश्नर मधुकर बोडके सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे, जिन्हें जलभराव की समस्या रोकने के लिए समयबद्ध तरीके से काम करने को कहा गया है।

सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव और स्वच्छता निर्देश

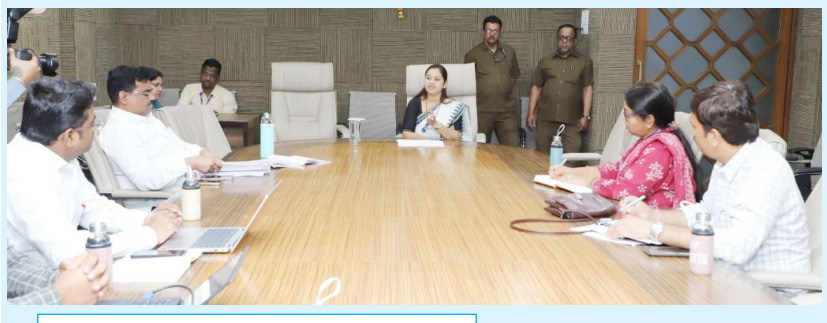

कचरा प्रबंधन और शहरव्यापी सफाई अभियान

बैठक में गीले और सूखे कचरे के पृथक्करण पर चर्चा करते हुए मेयर ने बताया कि स्लम इलाकों में इसका अनुपात कम है, जिसे बढ़ाने के लिए जन-जागरूकता अभियान की आवश्यकता है। वर्तमान में शहर की सड़कों की सफाई दो सत्रों में 1656 कर्मचारियों और 6 मैकेनिकल मशीनों द्वारा की जा रही है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की संकल्पना के तहत चल रहे 'महा स्वच्छता अभियान' को और प्रभावी बनाने के लिए मेयर ने आंतरिक सड़कों की नियमित सफाई और कचरा प्रसंस्करण (C&D वेस्ट और प्री-प्रोसेसिंग सेंटर) परियोजनाओं को गति देने का सुझाव दिया।

शहर के कुछ वार्डों से सार्वजनिक शौचालयों की नियमित सफाई न होने की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए मेयर ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि सफाई इंस्पेक्टर यह सुनिश्चित करें कि शौचालयों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो और पानी की टंकियां खाली होते ही तुरंत भरी जाएं। साथ ही, उन्होंने शौचालयों के दरवाजों और हैंडल्स की मरम्मत पर जोर देते हुए कहा कि बुनियादी सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बदलापुर से कसारा तक स्टेशनों का कायाकल्प

मध्य रेल के मुंबई मंडल ने स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में की वृद्धि

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

मुंबई मंडल ने जनवरी महीने में यात्रियों के घुटनों और समय का ख्याल रखते हुए 4 नए एस्केलेटर चालू कर दिए हैं। इसमें कसारा और बदलापुर स्टेशनों को 2-2 एस्केलेटर का तोहफा मिला है। साथ ही, वांगनी और बदलापुर में नई लिफ्ट भी लगाई गई हैं। अब बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए भारी सामान लेकर सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ेंगी।

बीएलडीसी पंखों का 'स्मार्ट' जादू

स्टेशनों पर अब कम शोर में ज्यादा हवा मिलेगी। रेलवे ने विभिन्न स्टेशनों पर 142 नए बीएलडीसी (BLDC) पंखे लगाए हैं और सैकड़ों पुराने पंखों को बदला है। इन पंखों की खासियत यह है कि ये बिजली की खपत को 50 से 70% तक कम कर देते हैं। यानी अब यात्री बिना पसीना बहाए और रेलवे बिना भारी बिजली बिल दिए, सफर का आनंद ले सकेंगे।

दादर स्टेशन पर 'विशालकाय' हवा का झोंका

भीड़भाड़ वाले दादर स्टेशन के लिए रेलवे ने खास इंतजाम किया है। यहाँ के प्लेटफॉर्मों पर 8 नए एचवीएलएस (HVLS) यानी 'हाई वॉल्यूम लो स्पीड' पंखे लगाए गए हैं। ये बहुत बड़े पंखे होते हैं जो धीरे घूमकर भी बड़ी मात्रा में हवा फेंकते हैं। इससे बड़े प्लेटफार्मों पर वेंटिलेशन बेहतर होगा और यात्रियों को भारी उमस से राहत मिलेगी।

ट्रेन की जानकारी अब 'क्रिस्टल क्लियर'

ट्रेन कब आएगी और कहाँ लगेगी, इसकी उलझन दूर करने के लिए लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) पर 4 नए डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं। वहीं हार्बर और मेन लाइन के नेरुल, पनवेल और शिवड़ी जैसे स्टेशनों पर 56 नए डिजिटल इंडिकेटर फिट किए गए हैं। ये नए बोर्ड देखने में सुंदर हैं और दूर से भी एकदम साफ दिखाई देते हैं, जिससे यात्रियों को भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी।

रोशनी ऐसी कि रात भी लगे दिन

सुरक्षा और स्पष्टता के लिए मुंबई के स्टेशनों पर रोशनी का 'नया अवतार' दिखा है। रेलवे ने 362 नई एलईडी लाइटें लगाई हैं और 1,600 से ज्यादा पुरानी लाइटों को बदल दिया है। ये लाइटें न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि इनकी लाइफ भी लंबी है। स्टेशन अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और चमकदार नजर आएंगे, जिससे रात के सफर में यात्रियों का डर खत्म होगा।

'नेताओं' की लगेगी क्लास

चिपलून में कांग्रेस का तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर

- पार्षद बनने से पहले सीखेंगे प्रशासन चलाने के गुर

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने कोकण के अपने उम्मीदवारों के लिए चिपलून में एक खास 'आवासीय शिविर' का इंतजाम किया है। शुक्रवार, 27 फरवरी से शुरू होने वाला यह शिविर 1 मार्च तक चलेगा। इसका सीधा मतलब है—उम्मीदवारों को तीन दिन तक वहीं रहकर राजनीति और समाजसेवा की 'एबीसीडी' समझनी होगी। इस शिविर में कोई छोटे-मोटे नेता नहीं, बल्कि

प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल देंगे जीत और विकास का मंत्र

खुद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल कमान संभालेंगे। उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और सामाजिक क्षेत्रों के माहिर खिलाड़ी भी मौजूद रहेंगे। यह कैंप केवल भाषणबाजी के लिए नहीं, बल्कि उम्मीदवारों को जमीन से जोड़ने के लिए लगाया जा रहा है।

शहर की समस्याओं का 'पोस्टमार्टम'

शिविर में चर्चा केवल वोटों पर नहीं होगी। छोटे शहरों और नगर पंचायतों में आने वाली असली मुसीबतें, जैसे—खराब सड़कें, पानी की किल्लत और कचरा मैनेजमेंट पर विशेषज्ञों से क्लास लगवाई जाएगी। उम्मीदवारों को सिखाया जाएगा कि प्रशासन से काम कैसे निकलवाना है और विकास की क्वालिटी से समझौता कैसे नहीं करना है।

'स्मार्ट पार्षद' बनाने का मिशन

कांग्रेस का लक्ष्य है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि केवल कुर्सी पर न बैठें, बल्कि जनता के प्रति संवेदनशील और जागरूक भी हों। एडवोकेट गणेश पाटील ने बताया कि यह ट्रेनिंग उम्मीदवारों को इतना सक्षम बना देगी कि वे अपने वार्ड या शहर के मुद्दों पर प्रशासन के साथ प्रभावी ढंग से 'फॉलो-अप' (पीछा करना) कर सकें।

कोकण के बाद अब पूरे महाराष्ट्र की बारी

यह तो बस शुरुआत है! कोकण विभाग के इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल होते ही, महाराष्ट्र के अन्य विभागों (जैसे विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र) के उम्मीदवारों के लिए भी ऐसे ही ट्रेनिंग कैंप लगाए जाएंगे। कांग्रेस का इरादा अपनी 'स्थानीय फौज' को इतना मजबूत करना है कि आगामी निकाय चुनावों में विरोधियों को कड़ी टक्कर दी जा सके।

विक्रोली में 500 बिस्तरों वाले आधुनिक अस्पताल का निर्माण

2028 तक काम पूरा करने का लक्ष्य

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

विक्रोली स्थित कन्नमवार नगर में 'क्रांतिवीर महात्मा ज्योतिबा फुले अस्पताल' को अब एक भव्य और आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। विधानसभा में विधायक सुनील राउत द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने जानकारी दी कि 1995 में बने इस पुराने अस्पताल की क्षमता अब 130 बेड से बढ़ाकर 500 बेड की जा रही है। स्थानीय नागरिकों की बढ़ती मांग को देखते हुए पुरानी इमारत को तोड़कर नई 21 मंजिला इमारत का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

निजीकरण की आशंकाओं पर विराम और प्रोजेक्ट की प्रगति

राज्य मंत्री ने सदन में स्पष्ट किया कि इस अस्पताल का किसी भी प्रकार का निजीकरण (Privatization) नहीं किया गया है और यहाँ मरीजों को पहले की तरह ही सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। प्रोजेक्ट की वित्तीय और तकनीकी स्थिति साझा करते हुए उन्होंने बताया कि म्हाडा (MHADA) को प्रीमियम और जमीन के लिए कुल 37 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में निर्माण कार्य का 12 प्रतिशत हिस्सा पूरा हो चुका है, जिसमें अस्पताल के साथ-साथ हॉस्टल और प्रशासनिक ब्लॉक की सुविधा भी शामिल होगी।

2028 तक लक्ष्य और स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली

सरकार ने इस महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य परियोजना को पूरा करने के लिए साल 2028 तक की समय-सीमा तय की है। माधुरी मिसाल ने आश्वासन दिया कि निर्माण कार्य निर्धारित योजना के अनुसार चल रहा है और म्हाडा ने जमीन का कब्जा भी सौंप दिया है। इस चर्चा में सदस्य अबू आज़मी ने भी हिस्सा लिया। अस्पताल के पूर्ण होने के बाद विक्रोली और आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी, जिससे मध्य मुंबई के स्वास्थ्य ढांचे को बड़ी मजबूती मिलेगी।

बेलासिस पुल का 'श्रीगणेश'

सीएम फडणवीस और डीसीएम शिंदे ने किया नवनिर्मित बेलासिस ब्रिज का उद्घाटन

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

- 120 करोड़ की लागत वाला यह पुल 4 महीने पहले हुआ तैयार

मुंबई सेंट्रल स्टेशन के पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले नवनिर्मित ओवरब्रिज का गुरुवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डिजिटल तरीके से उद्घाटन किया। बीएमसी (BMC) ने इस प्रोजेक्ट में कमाल की फुर्ती दिखाई है और निर्धारित समय से 4 महीने पहले ही पुल को जनता के लिए खोल दिया है। इस कामयाबी पर सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ने ही मनपा की जमकर तारीफ की। इस पुल के नाम को लेकर काफी चर्चा थी। पहले इसे समाज सुधारक नाना शंकर सेठ का नाम देने की बात चल रही थी, लेकिन उद्घाटन के वक्त मुख्यमंत्री फडणवीस

ने इसे 'पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होलकर' ब्रिज नाम देने की घोषणा की। कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने बताया कि ब्रिटिश कालीन मेजर जनरल जॉन बेलासिस के नाम वाले इस पुल का पुराना नाम अब पूरी तरह बदल दिया गया है।

ताडदेव और नागपाड़ा की दूरी हुई कम

यह नया ओवरब्रिज ताडदेव, नागपाड़ा और मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों को आपस में जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 333 मीटर है। पुल का पूर्वी हिस्सा लगभग 138 मीटर और पश्चिमी हिस्सा 157 मीटर लंबा है, जबकि रेलवे ट्रैक के ठीक ऊपर 36.90 मीटर का मुख्य हिस्सा (स्पैन) बनाया गया है। अब स्टेशन के दोनों तरफ आना-जाना काफी सुगम हो जाएगा।

पैदल चलने वालों का भी रखा गया ख्याल

करीब 120 करोड़ रुपए की लागत से बने इस ब्रिज को आधुनिक तकनीक से तैयार किया गया है। इसमें गाड़ियों के लिए 7 मीटर चौड़ा कैरिजवे (सड़क) तो है ही, साथ ही पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए दोनों तरफ चौड़े फुटपाथ भी बनाए गए हैं। रेलवे सीमा के भीतर काम करना काफी चुनौतीपूर्ण था, जिसे बीएमसी और रेलवे ने तालमेल बिठाकर रिकॉर्ड समय में पूरा किया।

स्पीड और क्वालिटी का नया उदाहरण: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार की नीति विकास कार्यों में 'स्पीड के साथ क्वालिटी' बनाए रखने की है। बीएमसी ने केवल 15 महीनों में इस पुल का निर्माण पूरा कर एक मिसाल कायम की है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी खुशी जताते हुए कहा कि यह ब्रिज शहर की यातायात व्यवस्था (ट्रैफिक) को सुचारू बनाने में बहुत मददगार साबित होगा।

डिजिटल 'पाटी-पेंसिल' का जमाना

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र राज्य 'स्मार्ट आंगनवाड़ी' योजना को लागू करने में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने विधान परिषद में जानकारी दी कि अब तक राज्य की 24,700 से अधिक आंगनवाड़ियों को 'स्मार्ट किट' वितरित की जा चुकी हैं। राज्य में कुल 1.10 लाख से अधिक आंगनवाड़ियाँ कार्यरत हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से इस योजना से जोड़ा जा रहा है। सरकार ने हर साल 5,000 नई आंगनवाड़ियों को स्मार्ट बनाने

महाराष्ट्र में 'स्मार्ट आंगनवाड़ी' अभियान और स्मार्ट किट का वितरण

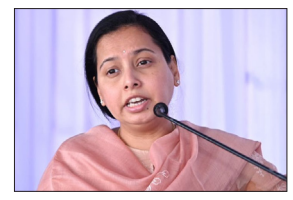

का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए प्रतिवर्ष लगभग 90 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।

पोषण और प्रशिक्षण में सुधार की नई पहल

नई शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को स्कूली शिक्षा विभाग के सहयोग से विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 'टेक होम राशन' (THR) के नियमों में बदलाव के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है। जनप्रतिनिधियों से मिले फीडबैक के आधार पर अब बच्चों को दिए जाने वाले भोजन के मेनू और गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा के समन्वय से राज्य की आंगनवाड़ियों को आधुनिक शिक्षण केंद्रों के रूप में विकसित करने की सरकार की मंशा है।

वितरण प्रक्रिया और बुनियादी ढांचे की अनिवार्यता

स्मार्ट किट प्राप्त करने के लिए संबंधित आंगनवाड़ी भवन का सरकारी स्वामित्व (मालिकाना हक) होना अनिवार्य है। मंत्री तटकरे ने स्पष्ट किया कि इस योजना के लिए तीन साल की निविदा (टेंडर) प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन प्रशासनिक मंजूरी और कार्य आदेश वित्तीय नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं। पालघर जैसे क्षेत्रों में जहां आंगनवाड़ी स्थानांतरण के मामले लंबित हैं, वहां जिला कलेक्टरों को प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, नई आंगनवाड़ियों के निर्माण के लिए जिला नियोजन समिति के 3% आरक्षित फंड से प्राथमिकता के आधार पर प्रावधान किया जाएगा।

जून तक भरे जाएंगे शिक्षकों के खाली पद

चंद्रकांत पाटील ने विधानसभा में किया ऐलान

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र के कॉलेजों में प्राध्यापकों की कमी अब बीते दिनों की बात होने वाली है। उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील ने विधान परिषद में विधायक अभिजित वंजारी के सवाल पर भरोसा दिलाया कि सरकार जून 2026 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश कर रही है। जिन कॉलेजों ने अपना 'रोस्टर' और 'एनओसी' का काम पूरा कर लिया है, वहां नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षकों के लिए एक और बड़ी खबर यह है कि कॉलेजों के प्राध्यापकों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की तैयारी है। इसका प्रस्ताव राज्य के वित्त विभाग को भेज दिया गया है। अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो अनुभवी शिक्षकों की सेवाएं दो साल और मिल सकेंगी। साथ ही, कला, विज्ञान और वाणिज्य कॉलेजों की तरह यहां भी वेतन और अनुदान के नियम लागू रहेंगे।

समाज कार्य कॉलेजों की 'घर वापसी'

मंत्री पाटिल ने बताया कि साल 2024 में 'समाज कार्य महाविद्यालयों' को समाज कल्याण विभाग से निकालकर उच्च शिक्षा विभाग में शामिल किया गया था। इस बदलाव के बाद शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रमोशन और सैलरी से जुड़े कई पेंच फंस गए थे। अब इन समस्याओं को सुलझाने के लिए बैठकों का दौर जारी है और चरणबद्ध तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं। शिक्षकों की मांगों को मानते हुए सरकार ने प्राध्यापकों के लिए 'कैश' योजना लागू कर दी है। इसके अलावा, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को अब चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना का भी फायदा मिल रहा है। सरकार अब 'आश्वसित प्रगति योजना' (10-20-30) और 'अर्जित अवकाश नकदीकरण' के प्रस्तावों को भी जल्द मंजूरी देने वाली है।

'सुपरफास्ट एक्सप्रेस-वे' पर दौड़ रहा है महाराष्ट्र : डीसीएम शिंदे

- देश के कुल विदेशी निवेश का 39% अकेले राज्य में, शिंदे ने गिनाई उपलब्धियां

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के बेरोजगार युवाओं के लिए पिटारा खोलते हुए साल 2026 को 'भर्ती वर्ष' (Recruitment Year) घोषित किया है। उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि 1.53 लाख पदों के लक्ष्य में से 85,363 नियुक्तियां पूरी हो चुकी हैं। अब बाकी बचे 75,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी। शिंदे ने साफ कहा कि अब 'स्थगन (Stay) की राजनीति' खत्म हो चुकी है और केवल 'तरक्की की दौड़' जारी है।

अजित दादा को याद कर भावुक हुए शिंदे

अपने भाषण की शुरुआत में शिंदे ने दिवंगत नेता अजित पवार को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अजित दादा के निधन से सदन पर दुख का साया है। दादा हमेशा 'डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स' में यकीन रखते थे और उनके इसी विजन को सरकार आगे ले जा रही है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि विकास की यह यात्रा अब किसी के रोके नहीं रुकेगी। आंकड़ों की बाजीगरी दिखाते हुए शिंदे ने बताया कि महाराष्ट्र आज भी देश में नंबर वन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। देश की कुल जीडीपी में राज्य का हिस्सा 13.5% है। साल 2024-25 में राज्य को 1,64,875 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश (FDI) मिला, जो पूरे भारत का 39% है।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

विभाग: उप जल अभियंता (परिरक्षण)
क्रमांक: ज.अ./9062/स.अ.(परि.) ज.का.पू.उ. दिनांक-25/02/26

ई-निविदा सूचना

बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु इच्छुक ठेकेदारों / निविदाकारों से ऑनलाइन ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदा वितरण एवं बिक्री की तिथि व समय तथा निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय का विस्तृत विवरण महानगरपालिका की आधिकारिक वेबसाइट http://portal.mcgm.gov.in तथा महाटेंडर पोर्टल http://mahatenders.gov.in पर 'निविदा अवलोकन' अनुभाग के अंतर्गत प्रकाशित / अपलोड की गई है।

क्रमांक	निविदा क्रमांक	निविदा का विषय:
1	2026_MCGM_1281615_1	कार्यकारी अभियंता (जल कार्य – निर्माण), पूर्व उपनगर विभाग के अंतर्गत स्टोर रूम में मोबाइल कॉम्पैक्टर स्टोरेज सुविधा का आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं संचालन (कमिशनिंग) का कार्य।

इच्छुक निविदाकार विस्तृत जानकारी के लिए महानगरपालिका की आधिकारिक वेबसाइट http://portal.mcgm.gov.in तथा महाटेंडर पोर्टल http://mahatenders.gov.in पर अवश्य देखें।

हस्ता/-
कार्यकारी अभियंता (प्र.का.)
जल कार्य विभाग

पीआरओ/3111/विज्ञा./2025-26

हल्का बुखार होने पर डॉक्टर से मिलें।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

(सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग)
देवनार मातृत्व गृह (गोवंडी) पूर्व, देवनार कॉलोनी, मुंबई-400043

क्र.एच.ओ./1116/डि.एम.एच. दिनांक 26.02.2025

विज्ञापन

विषय- एम पूर्व विभाग में जन स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत देवनार मातृत्व गृह (गोवंडी) में संविदा आधार पर ड श्रेणी के 06 (छह) रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में।

इसके द्वारा एम पूर्व विभाग के अंतर्गत महानगरपालिका में पंजीकृत स्थानीय गैर-सरकारी धर्मार्थ/बेरोजगारी संगठनों को सूचित किया जाता है कि देवनार मातृत्व गृह (गोवंडी) में ड श्रेणी के 6 (छह) अनुभवी संविदा कर्मचारियों (सफाईकर्मी, कुली आदि) की 6 महीने के लिए आवश्यकता है।

संविदा कर्मचारी उपलब्ध कराने के इच्छुक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) कार्यालय में जाकर **3630/- रुपए + 18% जीएसटी यानी 654/- रुपए कुल 4284/-** रुपए का भुगतान कर सकते हैं और आवेदन पत्र एवं चालान जन स्वास्थ्य विभाग, एम (पूर्वी) प्रभाग के अंतर्गत देवनार प्रसूति गृह के कार्यालय में 27.02.2026 से 10.03.2026 तक सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच जमा कर सकते हैं। निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि 13.03.2026 दोपहर 3:00 बजे तक है। निर्धारित कार्यालय समय के बाद जमा किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन अवकाशकालीन तिथियों को छोड़कर कार्यालय समय के दौरान नीचे दिए गए पते पर कार्यालय में जमा किए जाने चाहिए। इन आवेदनों की लॉटरी द्वारा देवनार प्रसूति गृह, गोवंडी के चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में चयन किया जाएगा।

पता- चिकित्सा अधिकारी,
देवनार मातृत्व गृह ,
गोवंडी म्युनिसिपल कॉलोनी,
गोवंडी, मुंबई-4000043

चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी)
देवनार मातृत्व गृह
गोवंडी, मुंबई ४३

पीआरओ/ 3122 /विज्ञा./2025-26

हल्का बुखार होने पर डॉक्टर से मिलें।

संपादकीय

हम आखिर जा कहाँ रहे हैं?

लखनऊ की वह दर्दनाक घटना, जिसमें नीट परीक्षा को लेकर हुए विवाद के बाद एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी, केवल एक अपराध कथा नहीं है। यह हमारे समय का कड़वा सच है। यह एक आईना है, जिसमें हमारा समाज, हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारी पारिवारिक सोच साफ दिखाई देती है। सवाल केवल यह नहीं कि एक घर में ऐसा क्यों हुआ; असली प्रश्न यह है कि ऐसा वातावरण क्यों बन रहा है जहाँ संवाद की जगह आक्रोश और अपेक्षाओं की जगह हिंसा खड़ी हो जाती है। नीट आज केवल एक परीक्षा नहीं रह गई है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा हमारे समाज में प्रतिष्ठा, सुरक्षा और सफलता का पर्याय बन चुकी है। लाखों परिवार अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देखते हैं। सपना देखना गलत नहीं है, पर जब सपना दबाव बन जाए और दबाव अपमान में बदल जाए, तब त्रासदी जन्म लेती है। बच्चे पढ़ाई से अधिक भय में जीने लगते हैं—असफल होने का भय, तुलना में पीछे रह जाने का भय, माता-पिता की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने का भय। लखनऊ जैसे शहर, जो शिक्षा और संस्कृति की पहचान रखते हैं, आज प्रतिस्पर्धा के तनाव से अछूते नहीं हैं। लखनऊ में घटी यह घटना पूरे देश की कहानी है। हर घर में लक्ष्य तय हैं, कोचिंग का समय तय है, अंक तय हैं; पर क्या संवाद का समय तय है? क्या किसी ने यह तय किया कि सप्ताह में एक दिन केवल बच्चे की मनःस्थिति पर बात होगी? हम बच्चों से पूछते हैं—कितने अंक आए? पर शायद ही पूछते हों—मन कैसा है? हमारी शिक्षा व्यवस्था ने सफलता को बहुत संकीर्ण परिभाषा दे दी है। डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी—मानो यही जीवन का अंतिम सत्य हो। कला, साहित्य, खेल, सामाजिक सेवा—इन सबको हम विकल्प नहीं, समझौता मानने लगे हैं। यह सोच बच्चों के भीतर एक अदृश्य दबाव बनाती है। जिनकी रुचि अलग है, वे भी उसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। परिणाम यह कि भीतर कुंठा बढ़ती है, आत्मसम्मान घटता है और संवाद की खिड़कियां बंद होने लगती हैं।

सबसे पीड़ादायक पहलू यह है कि परिवार, जो आश्रय होना चाहिए, वही तनाव का केंद्र बन रहा है। माता-पिता का उद्देश्य बुरा नहीं होता; वे अपने अनुभवों से बेहतर भविष्य देना चाहते हैं। परंतु अनुभव जब आदेश बन जाए और प्रेम जब अपेक्षा के बोझ तले दब जाए, तब संबंधों की जड़ें सूखने लगती हैं। बच्चे विरोध करते हैं, चुप हो जाते हैं या भीतर ही भीतर टूटते रहते हैं। और कभी-कभी यह टूटन असामान्य रूप ले लेती है।

हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य पर हमारी चुप्पी खतरनाक है। अवसाद, असफलता, चिंता—इन शब्दों को हम अभी भी कमजोरी मानते हैं। विद्यालयों में परामर्श की व्यवस्था सीमित है। घरों में भावनात्मक बातचीत दुर्लभ होती जा रही है। तकनीक ने सूचनाएं दी हैं, पर संवेदनाएं कम कर दी हैं। एक ही घर में रहते हुए भी लोग अपने-अपने परदों में बंद हैं। समाधान केवल कानून की कठोरता या दोषारोपण में नहीं है। समाधान आत्ममंथन में है। माता-पिता को यह समझना होगा कि बच्चा कोई परियोजना नहीं, एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है। उसे लक्ष्य दीजिए, पर उसके मन को भी सुनिए। असफलता को अपराध नहीं, अनुभव मानिए। विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा को अनिवार्य कीजिए। समाज को सफलता की बहुविध परिभाषा स्वीकार करनी होगी। लखनऊ की यह घटना हमें झकझोरती है। यह बताती है कि यदि हमने अपेक्षाओं को मानवीय नहीं बनाया, तो संबंधों की कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें तय करना है कि हम अंकों की अंधी दौड़ में रिश्तों को खो देंगे या संवाद और संवेदना को फिर से अपने घरों में स्थान देंगे। क्योंकि अंततः जीवन किसी भी परीक्षा से बड़ा है, और संबंध किसी भी रैंक से अधिक मूल्यवान।

भ्रष्टाचार का गहराता साया और सिसकते मानवीय मूल्य

धीरज सिंह
समाचार संपादक

शिक्षा का व्यवसायीकरण और ज्ञान के मानकों के साथ समझौता करना एक ऐसा भ्रष्ट आचरण है, जिसकी भरपाई दशकों तक नहीं की जा सकती। यदि बच्चों को परोसी जाने वाली सामग्री में ही पक्षपात या अनियमितता होगी, तो हम एक न्यायपूर्ण समाज की कल्पना कैसे कर सकते हैं? बौद्धिक ईमानदारी का अभाव ही वह बीज है जिससे प्रशासनिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार की फसलें लहलहाती हैं। यह एक ऐसा सूक्ष्म भ्रष्टाचार है जो समाज को मानसिक रूप से पंगु बना देता है।

आज के दौर में भ्रष्टाचार केवल सरकारी फाइलों या रुपयों के अवैध लेन-देन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह एक सामाजिक महामारी का रूप ले चुका है। हाल के दिनों में शैक्षिक संस्थानों और नीति-निर्धारक निकायों (जैसे एनसीईआरटी संबंधी विवाद) में भ्रष्टाचार की गूंज ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस दीमक ने राष्ट्र की नींव पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। जब समाज की सबसे पवित्र इकाई—शिक्षा—भ्रष्ट आचरण की चपेट में आती है, तो यह केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ी के साथ किया गया एक ऐतिहासिक विश्वासघात होता है। भ्रष्टाचार का यह व्यापक स्वरूप दर्शाता है कि हमने विकास की अंधी दौड़ में नैतिकता को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब यह प्रश्न केवल कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक अंतरात्मा की शुद्धि का बन गया है।

भ्रष्टाचार की जड़ें सीधे तौर पर मानवीय मूल्यों के क्षरण से जुड़ी हैं। मनुष्य के भीतर 'संतोष' और 'निस्वार्थ सेवा' जैसे गुणों का स्थान अब 'असीमित लोभ' और 'स्वार्थ' ने ले लिया है। जब व्यक्ति की सफलता का मापदंड उसके चरित्र के बजाय उसकी भौतिक संपत्ति बन जाती है, तो समाज अनैतिकता की ओर अग्रसर होने लगता है। ईमानदारी, करुणा और सत्यनिष्ठा जैसे मूल्य, जो कभी भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ थे, आज केवल किताबों तक सीमित होकर रह गए हैं। भ्रष्टाचार तब पनपता है जब एक व्यक्ति दूसरे के अधिकारों को छीनने में संकोच नहीं करता। यह मानवीय संवेदनाओं की मृत्यु का संकेत है, जहां एक डॉक्टर, इंजीनियर या अधिकारी अपने कर्तव्य से ऊपर निजी लाभ को प्राथमिकता देने लगता है, जिससे समाज का भरोसा बिखर जाता है।

बौद्धिक भ्रष्टाचार आज के समय का सबसे घातक पहलू बनकर उभरा है। जब सूचनाओं का प्रवाह करने वाली संस्थाएं या बौद्धिक वर्ग तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करता है, तो वह पूरे समाज की सोच को दूषित कर देता है। शिक्षा का व्यवसायीकरण और ज्ञान के मानकों के साथ समझौता करना एक ऐसा भ्रष्ट आचरण है, जिसकी भरपाई दशकों तक नहीं की जा सकती। यदि बच्चों को परोसी जाने वाली सामग्री में ही पक्षपात या अनियमितता होगी, तो हम एक न्यायपूर्ण समाज की कल्पना कैसे कर सकते हैं? बौद्धिक ईमानदारी का अभाव ही वह बीज है जिससे प्रशासनिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार की फसलें लहलहाती हैं। यह एक ऐसा सूक्ष्म भ्रष्टाचार है जो समाज को मानसिक रूप से पंगु बना देता है।

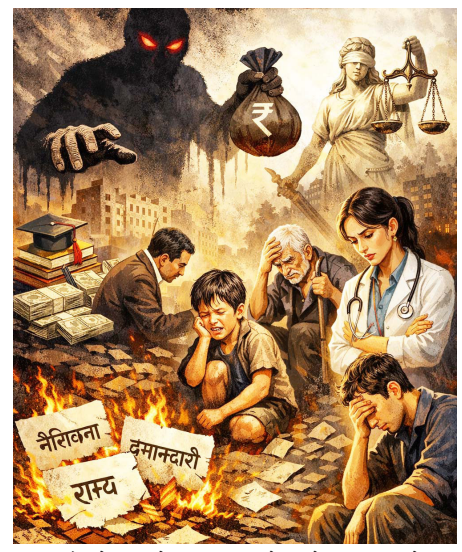

भ्रष्टाचार का सामाजिक प्रभाव अत्यंत विनाशकारी और दूरगामी होता है। यह न केवल आर्थिक असमानता को बढ़ाता है, बल्कि प्रतिभा और योग्यता का गला भी घोंट देता है। जब नियुक्तियों, ठेकों और संसाधनों के वितरण में भाई-भतीजावाद और रिश्वतखोरी का बोलबाला होता है, तो योग्य व्यक्ति हाशिए पर चला जाता है। इससे युवाओं में हताशा और व्यवस्था के प्रति आक्रोश पैदा होता है। समाज में 'शॉर्टकट' से सफलता पाने की संस्कृति विकसित हो जाती है, जो अंततः अराजकता को जन्म देती है। भ्रष्टाचार उस गरीब की थाली से निवाला छीन लेता है जिसके पास विरोध करने की शक्ति नहीं होती। यह लोकतंत्र की उन संस्थाओं को खोखला कर देता है, जिन पर आम आदमी का अटूट विश्वास टिका होता है।

इस विकट परिस्थिति से उबरने के लिए केवल कड़े कानून और न्यायिक सक्रियता पर्याप्त नहीं हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थानों का हस्तक्षेप भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अनिवार्य है, लेकिन वास्तविक समाधान 'नैतिक पुनर्जागरण' में निहित है। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में 'मूल्य-आधारित शिक्षा' को अनिवार्य रूप से शामिल करना होगा ताकि बचपन से ही सत्यनिष्ठा के बीज बोए जा सकें। जब तक समाज भ्रष्ट व्यक्तियों को महिमामंडित करना बंद नहीं करेगा और ईमानदारी को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगा, तब तक व्यवस्था परिवर्तन संभव नहीं है। प्रशासनिक पारदर्शिता और तकनीक का उपयोग भ्रष्टाचार को कम करने में सहायक हो सकते हैं, परंतु अंतिम जीत तभी होगी जब व्यक्ति के भीतर का नैतिक साहस जागृत होगा।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध केवल सरकार या न्यायपालिका की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक का कर्तव्य है। हमें आत्म-मंथन करना होगा कि क्या हम अपनी दैनिक जीवन की छोटी-छोटी सुख-सुविधाओं के लिए अपने मूल्यों से समझौता कर रहे हैं? भ्रष्टाचार मुक्त भारत का स्वप्न तभी साकार होगा जब हम 'स्व' (Self) से ऊपर 'सर्व' (Society) को रखेंगे। मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना ही वह एकमात्र मार्ग है जो हमें भ्रष्टाचार के इस दलदल से बाहर निकाल सकता है। भविष्य की पीढ़ियां हमें इस बात के लिए याद न रखें कि हमने उन्हें एक खोखला तंत्र दिया, बल्कि इसलिए याद रखें कि हमने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नैतिकता और सत्य के दीप को प्रज्वलित रखा।

हमारी गीता

कौरवों का शिष्टाचार, पांडव का समर्पण

स्वामिनी निष्कलानंदा
चिन्मय मिशन कल्याण

महाभारत के युद्ध का शंखनाद केवल एक सैन्य प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि दो अलग-अलग जीवन-दर्शनों का प्रकटीकरण था। एक ओर कौरवों की सेना थी, जहाँ अनुशासन और नियमों की चमक थी, तो दूसरी ओर पांडवों का पक्ष था, जहाँ प्रेम और आत्मीयता का अटूट बंधन था। अनुशासन का मुखौटा और खोखलापन कौरवों की सेना में शिष्टाचार (Protocol) का पूर्ण पालन दिखता है। भीष्म पितामह सरसेनापति थे, इसलिए पहला शंख उन्होंने बजाया। नियमबद्धता इतनी थी कि जब तक भीष्म लड़े, द्रोण शांत रहे; जब द्रोण आए, तो कर्ण दूर रहा। ऊपर से देखने पर यह व्यवस्था आदर्श लगती है, परंतु इसके भीतर ईर्ष्या, स्वार्थ और वैरभाव का विष भरा था। यह आज के उन परिवारों की तरह है जो बाहर से 'टीप-टॉप' दिखते हैं, लेकिन अंदर से वैचारिक रूप से बिखरे हुए हैं। यहाँ अनुशासन सम्मान से नहीं, बल्कि एक-दूसरे को नीचा दिखाने या अपनी बारी की प्रतीक्षा करने की मजबूरी से उपजा था।

दूसरी ओर पांडवों का दृश्य 'विचित्र' लग सकता है। उनके सेनापति धृष्टद्युम्न

थे, परंतु पहला शंख भगवान श्रीकृष्ण ने बजाया, जो केवल एक सारथी थे। धृष्टद्युम्न का नंबर बहुत बाद में आया। क्या यह अनुशासनहीनता थी? नहीं, यह आत्मबद्धता थी। पांडवों के लिए नियम से बड़ा प्रेम था और पद से बड़े कृष्ण थे। जहाँ गहरा प्रेम होता है, वहाँ 'मैं' और 'तू' का भेद मिट जाता है। वहां औपचारिकताएं (Formalities) दम तोड़ देती हैं। पांडवों की सेना एक ऐसे परिवार की तरह थी जहाँ दादा अपने पोते को आगे बढ़ाने में गर्व अनुभव करता है। यहाँ स्वार्थ नहीं, बल्कि एक-दूसरे के प्रति समर्पण था। कौरवों के पास प्रोटोकॉल था, पर पांडवों के पास ऐक्यभाव था।

आज हम अर्जुन बनने की बात तो करते हैं, पर हमारी नीति अक्सर दुर्योधन वाली होती है। हम रिश्तों में शिष्टाचार तो ढूंढते हैं, पर समर्पण भूल जाते हैं।

शख्सियत

चंद्रशेखर आज़ाद

भारत का अमर क्रांतिकारी

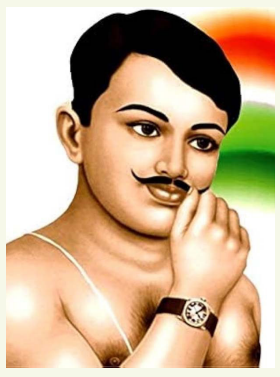

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र हैं, जिनकी चमक ने दासता की काली रातों में करोड़ों भारतीयों को आजादी का मार्ग दिखाया।

23 जुलाई, 1906 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव भाबरा में जन्मे चंद्रशेखर का बचपन अभावों में तो बीता, लेकिन उनके संस्कार और दृढ़ इच्छाशक्ति ने उन्हें बचपन से ही असाधारण बना दिया था। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 1921 का असहयोग आंदोलन था, जब मात्र 15 वर्ष की अल्पायु में वे गांधीजी के आह्वान पर सड़कों पर उतर आए। जब उन्हें गिरफ्तार कर कचहरी में पेश किया गया, तो उन्होंने निडर होकर अपना नाम 'आज़ाद', पिता का नाम 'स्वतंत्रता' और घर का पता 'जेल' बताया। इस बालक की निर्भीकता देखकर अंग्रेज जज भी दंग रह गया, लेकिन सजा के तौर पर उन्हें 15 कोड़े मारने का आदेश दिया गया। हर कोड़े की मार पर चंद्रशेखर के मुँह से 'वंदे मातरम्' और 'भारत माता की जय' का उद्घोष निकला, जिसने उन्हें रातों-रात पूरे देश का चहेता 'आज़ाद' बना दिया। यह घटना उनके जीवन की आधारशिला बनी, जहाँ से उन्होंने कसम खाई कि वे ताउम्र कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आएंगे।

असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित होने से आज़ाद का मोह अहिंसात्मक संघर्ष से भंग हो गया और उन्होंने सशस्त्र क्रांति का मार्ग चुना। वे 'हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' (HRA) से जुड़े और राम प्रसाद बिस्मिल व अशफाक उल्ला खाँ जैसे दिग्गजों के मार्गदर्शन में क्रांतिकारी गतिविधियों को धार दी। 1925 का प्रसिद्ध 'काकोरी कांड' उनके साहस का प्रमाण था, जहाँ उन्होंने सरकारी खजाने को लूटकर क्रांतिकारी आंदोलन के लिए संसाधन जुटाए। बिस्मिल की शहादत के बाद, संगठन बिखरने लगा था, लेकिन आज़ाद ने अपनी अद्भुत नेतृत्व क्षमता से इसे पुनर्जीवित किया। उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे युवा क्रांतिकारियों के साथ मिलकर 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' (HSRA) की स्थापना की। आज़ाद केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार और संगठनकर्ता भी थे। वे भेष बदलने में इतने माहिर थे कि कई बार पुलिस के घेरे के बीच से साधु या श्रमिक बनकर निकल जाते थे। उन्होंने झाँसी के पास ओरछा के जंगलों में 'हरिशंकर ब्रह्मचारी' बनकर लंबे समय तक क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया, जिससे अंग्रेज खुफिया तंत्र पूरी तरह नाकाम रहा।

27 फरवरी, 1931 का वह दिन भारतीय इतिहास के सबसे भावुक क्षणों में से एक है, जब प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद को उनके एक मुखबिर की गद्दारी के कारण पुलिस ने घेर लिया। भारी पुलिस बल और अत्याधुनिक हथियारों के सामने आज़ाद अकेले अपनी छोटी सी पिस्तौल 'बमतुल बुख' के साथ डटे रहे। उन्होंने अपने साथी सुखदेव राज को तो सुरक्षित निकाल दिया, लेकिन खुद अंत तक लड़ते रहे। जब उनकी पिस्तौल में केवल एक गोली शेष बची, तो उन्होंने अपनी वह पुरानी प्रतिज्ञा दोहराई कि वे कभी जीवित गिरफ्तार नहीं होंगे।

जीवन ऊर्जा

सिनेमा की एक कालजयी अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर का जन्म 27 फरवरी, 1932 को लंदन के हैम्पस्टेड में एक अमेरिकी परिवार में हुआ था। उन्होंने मात्र 10 वर्ष की अल्पायु में अपनी पहली फिल्म से अभिनय की शुरुआत की और अपनी प्रतिभा के दम पर हॉलीवुड के 'स्वर्ण युग' (Golden Age) की सबसे बड़ी और चमकदार सितारा बन गईं।

एलिजाबेथ टेलर: जन्म - 27 फरवरी, 1932

जन्म

इंसान को अपने अतीत से जीना नहीं चाहिए

मैंने केवल उन्हीं पुरुषों से शादी की, जिनसे मैंने प्यार किया। कितनी महिलाएँ ऐसा कह सकती हैं? सफलता एक बेहतरीन डिओडोरेंट है। यह आपकी पिछली सारी गलतियों को मिटा देती है। प्यार में गिरना आसान है, लेकिन प्यार में बने रहना ही असली चुनौती है। एक औरत का दिल गहरा सागर होता है, जिसमें कई राज छिपे होते हैं। शादी एक ऐसा बंधन है जिसे दो लोग मिलकर निभाते हैं, अगर प्यार सच्चा हो। मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी पुरुष के साथ केवल समय बिताने के लिए रिश्ता नहीं रखा। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, एक बार टूट जाएं तो उन्हें जोड़ना मुश्किल होता है। सच्चा प्यार वह है जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। इंसान को अपने अतीत से सीखना चाहिए, लेकिन उसमें जीना नहीं चाहिए। बड़ी लड़कियों को बड़े डायमंड्स की ज़रूरत होती है। आप एक अच्छे दोस्त और अच्छे हीरे को कभी नहीं छोड़ सकते। गहने केवल सजावट नहीं, बल्कि यादों का पिटारा होते हैं। सुंदरता केवल त्वचा तक सीमित नहीं होती, यह आपके व्यक्तित्व से झलकती है। मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, मुझे चमकती चीज़ें पसंद हैं। हीरे हमेशा के लिए होते हैं, और मेरी दोस्ती भी। अपना ड्रिंक डालो, थोड़ा लिपस्टिक लगाओ और खुद को संभालो। जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। मैं एक सर्वाइवर हूँ, मैं हार नहीं मानती। जब तक आप कोशिश कर रहे हैं, आप असफल नहीं हैं। हिम्मत वह है जो आपको डर के बावजूद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हर दिन एक नया अवसर है, इसे बर्बाद न करें। मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, और मुझे उन पर पछतावा नहीं है। जीवन छोटा है, इसे अपनी शर्तों पर जियो। अभिनय करना मेरे लिए सांस लेने जैसा है। प्रसिद्धि एक दोधारी तलवार है, इसे संभालना सीखना पड़ता है।

अपने विचार

शंकराचार्य के शिविर में सपा और कांग्रेस से जुड़े कई कद्दावर नेताओं का आना-जाना लगा रहता था। जांच का विषय यह भी होना चाहिए कि क्या ये नेता भी बटुकों के साथ हुए कुकर्मों में शामिल थे। शंकराचार्य के धरने को एक उपमुख्यमंत्री का समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने आश्वासन दिया था कि जब तक वे खुद आकर पानी न पिलाएं, धरना जारी रखा जाए।

आशुतोष ब्रह्मचारी
महंत, शाकंभरी पीठ

सरकार एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत शंकराचार्य को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार शंकराचार्य साक्षात भगवान के स्वरूप माने जाते हैं। ऐसे में उन पर 'पॉक्सो' जैसे गंभीर और विवादास्पद मुकदमे दर्ज करना न केवल उनकी छवि धूमिल करना है!

अजय राय
नेता, कांग्रेस

अब बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। यहां भी भाजपा की सरकार बनेगी और सरकार का पहला काम यह होगा कि सीमा पर बाड़ का काम समाप्त करना और सभी अवैध घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर का रास्ता दिखाया जाए। यह हमारा चुनावी वादा नहीं बल्कि सरकार की घोषणा है।

अमित शाह
गृहमंत्री, भारत सरकार

यह एक हिंदू राष्ट्र है। यहां किसी को भी ऐसा करने की इजाज़त नहीं है... क्या इन लोगों को मालेगांव के विकास के लिए चुना गया है या जिहाद करने के लिए? ऐसी संस्थाओं को भंग करने की मांग क्यों नहीं की जानी चाहिए? जब इतनी सारी मस्जिदें हैं तो वे वहां नमाज़ क्यों पढ़ें? हम निश्चित रूप से कार्रवाई की मांग करेंगे।

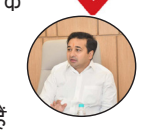

नितेश राणे
मंत्री, महाराष्ट्र

सर्वसिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ बिजाना शाजापुर मध्यप्रदेश

जीवन का वास्तविक धन : विचार, व्यवहार और विद्या

भारतीय मनीषा और आचार्य चाणक्य के नीति-सूत्र केवल शब्दों का संग्रह नहीं हैं, बल्कि ये जीवन जीने की एक ऐसी कला सिखाते हैं जो सदियों बाद आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इन सूत्रों में व्यक्ति के चरित्र निर्माण, सामाजिक व्यवहार, स्वास्थ्य और अध्यात्म का जो अद्भुत समन्वय मिलता है, वह किसी भी मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में सक्षम है। आइए, इन महान विचारों के माध्यम से जीवन की गहराई को समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी समाज में व्यक्ति की महत्ता उसके धन या कुल से नहीं, बल्कि उसके गुणों और उसकी विद्वत्ता से आंकी जाती है। चाणक्य कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई महान नहीं हो जाता, यदि उसके पास विद्या नहीं है। वह तो उस पलाश के फूल की तरह है जो दिखने में तो अत्यंत सुंदर और चटकीला है, परंतु सुगंधहीन होने के कारण किसी काम का नहीं। इसके विपरीत, एक नीच कुल में जन्मा विद्वान व्यक्ति भी देवताओं द्वारा पूजा जाता है। विद्या ही वह वास्तविक आभूषण है जो रूप और यौवन की नश्वरता के पार व्यक्ति को अमर बनाती है। सफलता तभी सार्थक है जब वह विद्या को सुशोभित करे, और विद्वान व्यक्ति की प्रतिष्ठा केवल उसके घर या देश तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसे पूरे विश्व में गौरव प्राप्त होता है।

पंडित कैलाशचंद्र शर्मा
वैदिक सनातन संस्कृति के प्रचारक व सर्व सिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ के संस्थापक।
मो. नं. 9425980556

मानव जीवन में 'जैसा अन्न, वैसा मन' का सिद्धांत अत्यंत प्रभावशाली है। जिस प्रकार दीपक अंधकार का भक्षण करता है और प्रतिक्रिया स्वरूप काला धुआं (काजल) उत्पन्न करता है, उसी प्रकार हम जिस श्रेणी का भोजन करते हैं, हमारे विचार भी उसी प्रकृति के बनते हैं। सात्विक भोजन सात्विक बुद्धि और शांति प्रदान करता है, जबकि तामसिक भोजन विचारों में मलिनता लाता है। इसके साथ ही, स्वास्थ्य के लिए जल के महत्व को भी रेखांकित किया गया है। आयुर्वेद का यह सूत्र कि भोजन के तुरंत बाद पानी पीना विष के समान है और भोजन पचने के बाद पानी पीना बल देने वाला है, आज के आधुनिक विज्ञान में भी मान्य है। यह अनुशासन न केवल हमारे शरीर को रोगों से मुक्त रखता है, बल्कि हमारी मानसिक ऊर्जा को भी संतुलित बनाए रखता है।

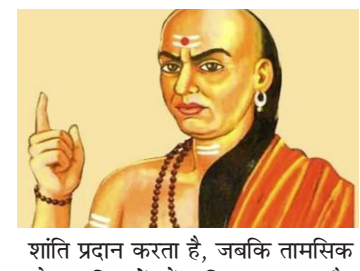

अध्यात्म के क्षेत्र में अक्सर हम बाहरी कर्मकांडों को ही सर्वोपरि मान लेते हैं, किंतु वास्तविक सत्य हमारे 'भाव' में छिपा है। ईश्वर न तो काठ में हैं, न पत्थर में और न ही मिट्टी की प्रतिमा में; वे तो भक्त के हृदय के भाव में वास करते हैं। यदि मन में श्रद्धा और भाव नहीं है, तो वेद मंत्रों का उच्चारण और बड़े-बड़े यज्ञ भी निष्फल हो जाते हैं। ज्ञान की सार्थकता भी तभी है जब उसे क्रियान्वित किया जाए। क्रियाहीन ज्ञान उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे सेनापति के बिना सेना। साथ ही, यज्ञ और अनुष्ठान तभी पूर्ण माने जाते हैं जब उनमें दान और सेवा का तत्व शामिल हो। दूसरों का कल्याण करने वाला राजा और संतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण ही अपने धर्म में शुद्ध माना गया है।

आज की भागदौड़ और गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग में 'संतोष' ही वह एकमात्र औषधि है जो मानसिक शांति दे सकती है। चाणक्य के अनुसार, संयमित मन से बड़ा कोई तप नहीं और संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। लोभ एक ऐसा व्याधि (रोग) है जो कभी शांत नहीं होता, जबकि दया सबसे बड़ा धर्म है। क्रोध साक्षात् यमराज है और तृष्णा उस वैतरणी नदी के समान है जो मनुष्य को दुखों के नर्क की ओर ले जाती है। जिसके जीवन में संतोष का उदय हो गया, उसके लिए यह संसार ही नंदनवन बन जाता है। धन की वास्तविक शोभा उसके संचय में नहीं, बल्कि सुपात्र को दान देने और उचित उपभोग में है। जो व्यक्ति इन नीतियों को समझकर अपने जीवन में ढाल लेता है, वह न केवल स्वयं सफल होता है, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है।

अपने विचार
डीबीडी कार्यालय
ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के.के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001
indiagroundreport@gmail.com
भेज सकते हैं।

यह अखबार "माध्यम कार्पोरेट सर्विसेज लि." के लिए प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक अरुण लाल द्वारा ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के. के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001 से प्रकाशित एवं सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नं. 4, एन.के.इंडस्ट्रियल इस्टेट, इनसाइड प्रवासी इंडिस्ट्रयल इस्टेट गेट नं. 2, गोरेगांव पू., मुंबई-63 से मुद्रित. फोन नं. 022-66555719 ईमेल : indiagroundreport@gmail.com **कार्यकारी संपादक :** अमित बृज (पी.आर.बी. अधिनियम के अंतर्गत खबरों के चयन के लिए ज़िम्मेदार).

ब्रीफ न्यूज़

संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान में ठाणे की ग्राम पंचायतों को सम्मान

ठाणे। संत गाडगे बाबा के स्वच्छता विचारों पर आधारित संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक चयनित ग्राम पंचायतों के लिए 25 फरवरी 2026 को कोंकण डिवीजन के डिविजनल कमिश्नर डॉ. विजय सूर्यवंशी की अध्यक्षता में सिडको कार्यालय ऑडिटोरियम, नवी मुंबई में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर जिला परिषद ठाणे की उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया। वर्ष 2022-23 के डिविजनल स्तर प्रतियोगिता में वडपे (भिवंडी) ग्राम पंचायत को द्वितीय स्थान के साथ 9 लाख रुपये तथा जांभुल (कल्याण) ग्राम पंचायत को तृतीय स्थान के साथ 7 लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। पंचायतों को स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, सीवेज योजना, जनभागीदारी और जागरूकता अभियानों में उत्कृष्ट कार्य के लिए सराहा गया। इसी कार्यक्रम में महा आवास अभियान 2023-24 के तहत राज्य प्रायोजित घरकुल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला परिषद ठाणे को 'सर्वश्रेष्ठ जिला – तृतीय पुरस्कार' तथा मणिवली ग्राम पंचायत को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने ठाणे जिले की स्वच्छता और ग्रामीण विकास क्षेत्र में निरंतर प्रगति की सराहना करते हुए भविष्य में भी जनसहभागिता के साथ विकास कार्य आगे बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया।

विश्व मराठी भाषा दिवस: प्राचीन मराठी भाषा विषयक व्याख्यान

ठाणे। विश्व मराठी भाषा दिवस के अवसर पर मराठी भाषा की समृद्ध परंपरा और ऐतिहासिक विरासत को रेखांकित करने के लिए शुक्रवार शाम 4 बजे मनपा के स्वर्गीय नरेंद्र बल्लाल ऑडिटोरियम में 'प्राचीन मराठी भाषा' विषय पर वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार श्रीकांत बोजेवार का व्याख्यान आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मेयर शर्मिला पिंपलोलकर, डिप्टी मेयर कृष्णा पाटिल, हाउस के नेता हनमंत जगदाले सहित मनपा के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। व्याख्यान में मराठी भाषा की उत्पत्ति, संस्कृत और प्राकृत से संबंध, संत साहित्य की परंपरा, शिव और पेशवा काल में भाषा की भूमिका तथा आधुनिक दौर में इसके बदलते स्वरूप पर विस्तृत प्रकाश डाला जाएगा। साथ ही ज्ञानेश्वर और तुकाराम जैसे संतों के साहित्य से भाषा को मिले गौरव पर चर्चा होगी। मनपा ने विद्यार्थियों, साहित्य प्रेमियों और नागरिकों से बड़ी संख्या में उपस्थित होकर मराठी भाषा के संरक्षण और संवर्धन के इस प्रयास में सहभागिता की अपील की है।

'घर नहीं तो एक इंच भी नहीं हिलेंगे'

▸▸ शाहू नगर निवासियों का ट्रांजिट कैंप जाने से इनकार

▸▸ लोगों ने डीआरपी और अडानी कंपनी को जाने की दी चेतावनी

दीपक पवार । मुंबई

माहिम ईस्ट स्थित शाहू नगर कॉलोनी के लोगों ने धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। शनिवार को हुई एक बड़ी पब्लिक मीटिंग में लोगों ने साफ कर दिया कि वे अपना पक्का घर छोड़कर किसी 'ट्रांजिशन कैंप' में धक्के खाने नहीं जाएंगे। निवासियों का सीधा सवाल है— जब रहने का ठिकाना ही तय नहीं, तो हम अपनी जगह क्यों छोड़ें? शाहू नगर डेवलपमेंट कमिटी ने अडानी कंपनी को साफ चेतावनी दी है कि वे यहाँ जबरदस्ती करने की कोशिश न करें।

बिना 'नक्शे' के उजाड़ने की तैयारी?

लोकल कॉर्पोरेटर हर्षला मोरे ने मीटिंग में प्रोजेक्ट की पोल खोलते हुए कहा कि धारावी रीडेवलपमेंट का 'मास्टर प्लान' अभी तक कागज पर भी नहीं उतरा है। सरकार और अडानी कंपनी ने अभी तक यह पब्लिश नहीं किया है कि किसे घर कहाँ और कितना बड़ा मिलेगा। ऐसे में लोगों को उनके पक्के घरों से निकालकर ट्रांजिट कैंप में भेजना सरासर अन्याय है। जब तक हर परिवार के हाथ में नए घर की चाबी नहीं आ जाती, शाहू नगर का कोई भी सदस्य वहां से नहीं हटेगा।

एकजुटता का 'महा-संकल्प'

शाहू नगर टेनेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण जाधव और चार्ली एंथनी ने निवासियों से अपील की कि यह समय घर में बैठने का नहीं बल्कि सड़क पर उतरने का है। उन्होंने कहा, हम पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं, हमें फिर से किसी कैंप में भेजकर बेघर करना मंजूर नहीं। मीटिंग में मौजूद हजारों लोगों ने एक सुर में कहा कि हमारा पुनर्वास शाहू नगर में ही होना चाहिए। एकता का संदेश देते हुए चेतावनी दी गई कि आने वाले दिनों में अडानी कंपनी के खिलाफ एक बड़ा जन-आंदोलन खड़ा किया जाएगा।

कोली समाज का गुस्सा और अडानी पर वार

मीटिंग में कोली समाज के प्रतिनिधियों ने अपना दर्द और गुस्सा दोनों जाहिर किया। जोसेफ कोली ने कहा कि शाहू नगर धारावी की सबसे शांत और बेहतरीन कॉलोनी है, लेकिन अडानी और DRP ने यहाँ के कोली समाज को बहुत तकलीफ दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि डेवलपमेंट के नाम पर उन्हें उनके मूल स्थान से बेदखल करने की साजिश रची जा रही है। समाज के लोगों ने तय किया है कि वे इस 'अन्याय' के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे।

दिग्गजों का समर्थन और अशांति का माहौल

इस विरोध प्रदर्शन में विधायक बाबूराव माने, आशीष मोरे और 'धारावी बचाओ' आंदोलन के कई बड़े नेता शामिल हुए। शाहू नगर के कोने-कोने में इस वक्त अशांति और गुस्से का माहौल है। लोगों का कहना है कि वे डेवलपमेंट के विरोधी नहीं हैं, लेकिन अडानी कंपनी के अस्पष्ट इरादों पर उन्हें भरोसा नहीं है। धारावी के सेक्टर 1 के निवासियों ने कमर कस ली है और संकेत दे दिए हैं कि प्रशासन की किसी भी जबरदस्ती का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा।

महावितरण कंपनी को मिला 'बिग इंपैक्ट अवॉर्ड'

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

महाराष्ट्र में तकनीकी नवाचार और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए महावितरण को प्रतिष्ठित 'बिग इम्पैक्ट' अवॉर्ड से नवाजा गया है। मुंबई के होटल सहारा स्टार में आयोजित भव्य समारोह में, प्रसिद्ध रेडियो चैनल 92.7 बिग FM ने महावितरण को यह सम्मान प्रदान किया। महावितरण की ओर से कार्यकारी निदेशक धनंजय औंधेकर, मुख्य अभियंता प्रवीण परदेशी और मुख्य जनसंपर्क अधिकारी भरत पवार ने मुंबई की मेयर श्रीमती रितु तावड़े और अभिनेत्री ईशा देओल के हाथों यह पुरस्कार ग्रहण किया। इस कार्यक्रम में आईटी मंत्री आशीष शेलार और अभिनेता बोम्मन ईरानी सहित कई गणमान्य हस्तियां मौजूद रहीं।

स्मार्ट मीटरिंग में महाराष्ट्र बना देश का अग्रणी राज्य

महाराष्ट्र ने पूरे देश में रिकॉर्ड 88.50 लाख आधुनिक स्मार्ट मीटर लगाकर पहला स्थान हासिल किया है। इस ऐतिहासिक सफलता में महावितरण की कार्यक्षमता और नियोजन की सबसे बड़ी भूमिका रही है। ये स्मार्ट मीटर ग्राहकों को न केवल 100 प्रतिशत सटीक बिलिंग सुनिश्चित करते हैं, बल्कि उन्हें हर घंटे अपने मोबाइल पर बिजली के इस्तेमाल को ट्रैक करने की सुविधा भी देते हैं। खास बात यह है कि महावितरण द्वारा ये मीटर पूरी तरह से नि:शुल्क लगाए जा रहे हैं, जिससे आम जनता पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ रहा है।

उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक लाभ और विशेष रियायतें

नई स्मार्ट मीटर प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली बचत के साथ-साथ आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। घरेलू ग्राहकों को उनके दैनिक बिजली उपयोग पर 80 पैसे प्रति यूनिट का 'TOD डिस्काउंट' दिया जा रहा है। साथ ही, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच बिजली इस्तेमाल करने पर विशेष रियायती दरें लागू की गई हैं। इस तकनीक को जन-जन तक पहुँचाने के लिए 9 से 23 फरवरी तक पूरे राज्य में 'जागरूकता पखवाड़ा' भी मनाया गया, ताकि लोग स्मार्ट मीटर के फायदों को समझ सकें।

अब शनिवार-रविवार को भी मिलेगी ठंडी हवा

पश्चिम रेलवे की एसी लोकल सेवाओं में भारी बढ़ोतरी

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

मुंबई की जीवनरेखा मानी जाने वाली लोकल ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने वातानुकूलित (एसी) सेवाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, वर्तमान में कार्यदिवसों (सोमवार से शुक्रवार) में कुल 133 एसी लोकल सेवाएं संचालित की जा रही हैं। यात्रियों को राहत देने के लिए जनवरी और फरवरी माह में चरणबद्ध तरीके से 12-12 नई एसी सेवाएं जोड़ी गईं, जिससे अब नेटवर्क पर वातानुकूलित सफर पहले से कहीं अधिक सुलभ हो गया है।

सप्ताहांत यात्रियों के लिए आरामदायक सफर का उपहार

अक्सर सप्ताहांत पर कम होने वाली सेवाओं के विपरीत, पश्चिम रेलवे अब शनिवार और रविवार को भी 106 एसी लोकल सेवाएं चला रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन यात्रियों को सुविधा देना है जो अवकाश, निजी काम या कार्यालय के सिलसिले में वीकेंड पर यात्रा करते हैं। सप्ताहांत में इन अतिरिक्त सेवाओं की उपलब्धता से न केवल भीड़ कम हुई है, बल्कि यात्रियों को एक प्रीमियम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिल रहा है, जिसे मुंबईकरों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।

भीषण गर्मी से राहत और बेहतर यात्रा गुणवत्ता का संकल्प

आगामी ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए एसी सेवाओं का यह विस्तार यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। पश्चिम रेलवे ने स्पष्ट किया है कि वह सुरक्षित, कुशल और यात्री-अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। एसी लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाना दैनिक यात्रा की गुणवत्ता में सुधार करने और मुंबई के उपनगरीय रेल नेटवर्क को आधुनिक बनाने के निरंतर प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

रेलवन ऐप : एकीकृत डिजिटल टिकटिंग का नया युग

▸▸ यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप 1 मार्च से होगा बंद

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

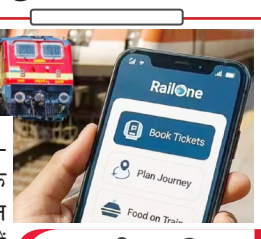

यात्रियों की सुविधा और डिजिटल सेवाओं के एकीकरण के उद्देश्य से भारतीय रेलवे ने 'रेलवन ऐप' को एक समग्र डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया है। इस ऐप के जरिए रेल यात्रा से जुड़ी लगभग सभी प्रमुख सेवाएं अब एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। रेलवे का लक्ष्य यात्रा प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाना है। रेलवे प्रशासन ने निर्णय लिया है कि अब तक अनारक्षित टिकट बुकिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप 1 मार्च 2026 से बंद कर दिया जाएगा। अनारक्षित टिकट बुकिंग की सुविधा पूरी तरह रेलवन ऐप में समाहित कर दी गई है। फिलहाल रेलवन ऐप पर अनारक्षित टिकटों की बुकिंग पर 14 जून 2026 तक 3 प्रतिशत की छूट प्रायोगिक तौर पर दी जा रही है।

मौजूदा यूजर आईडी से ही लॉगिन

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के वर्तमान उपयोगकर्ता अपनी मौजूदा यूजर आईडी के माध्यम से सीधे रेलवन ऐप पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए नए सिरे से पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे यात्रियों का डेटा और सुविधा दोनों सुरक्षित रहेंगे।

सीज़न टिकट ट्रांसफर की सुविधा

यूटीएस ऐप पर पहले से बुक किए गए सीज़न टिकटों के लिए 'Show Ticket' सेक्शन में "Transfer Ticket" का नया विकल्प जोड़ा गया है। इसके जरिए यात्री अपने सीज़न टिकट को रेलवन ऐप पर आसानी से स्थानांतरित कर सकेंगे।

एक ही मंच पर सभी सेवाएं

रेलवन ऐप के माध्यम से आरक्षित और अनारक्षित टिकट बुकिंग, प्लेटफॉर्म टिकट, लाइव ट्रेन स्टेटस, पीएनआर जांच, टिकट निरस्तीकरण एवं रिफंड, रेल मदद सेवाएं, शिकायत दर्ज करना और ट्रेन में भोजन बुकिंग जैसी सुविधाएं एकीकृत रूप से उपलब्ध कराई गई हैं। अब यात्रियों को अलग-अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी।

सिंगल साइन-ऑन और ई-वॉलेट सुविधा

ऐप की खास विशेषता सिंगल साइन-ऑन है। यात्री पूर्व में उपयोग की गई रेलकनेक्ट या यूटीएस ऑन मोबाइल की आईडी से ही लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ रेलवे ई-वॉलेट की सुविधा भी दी गई है, जिसके जरिए अनारक्षित टिकट लेने पर 3 प्रतिशत तक की छूट मिलती है। रेलवन ऐप के जरिए रेलवे सेवाओं में पारदर्शिता और सुगमता बढ़ाने का प्रयास किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय आर्बोरीकल्चर परिषद का आयोजन

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

मुंबई के होटल सहारा स्टार में 6 से 8 मार्च के बीच दूसरी अंतरराष्ट्रीय आर्बोरीकल्चर (वृक्ष संरक्षण) परिषद का आयोजन होने जा रहा है। नानाजी देशमुख प्रतिष्ठान और ATCA द्वारा आयोजित इस तीन दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन राज्य की पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे करेंगी, जबकि समापन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों होगा। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य शहरों में केवल पेड़ लगाना ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से मौजूदा पेड़ों के संरक्षण की तकनीक को बढ़ावा देना है।

नीति निर्धारण के लिए 'आर्बोरीकल्चर इम्पैक्ट सर्वे' पर जोर

ATCA के संचालक वैभव राजे ने स्पष्ट किया कि विकास परियोजनाओं के दौरान केवल सामाजिक सर्वेक्षण ही काफी नहीं है, बल्कि 'आर्बोरीकल्चर इम्पैक्ट सर्वे' अनिवार्य होना चाहिए। पश्चिमी देशों की तर्ज पर भारत में भी नीतिगत बदलाव लाने की आवश्यकता है ताकि कोई भी निर्माण कार्य शुरू होने से पहले पेड़ों के संरक्षण की ठोस योजना बने। इस परिषद में निकलने वाले निष्कर्षों और सिफारिशों को केंद्र एवं राज्य सरकार को भेजा जाएगा ताकि भविष्य की शहरी नीतियों में इन्हें शामिल किया जा सके।

वैश्विक और राष्ट्रीय विशेषज्ञों का महाकुंभ

इस परिषद में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के नामचीन पर्यावरण प्रेमी और आर्बोरीकल्चर विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। प्रमुख वक्ताओं में आर्बर डे फाउंडेशन (USA) के सीईओ डैन लैम्बे और बोर्ड ऑफ आर्बोरीकल्चर (ऑस्ट्रेलिया) के निदेशक कार्ल डल्ला रिवा शामिल हैं। इनके साथ ही देश की विभिन्न महानगरपालिकाओं के प्रतिनिधि, एयरपोर्ट डेवलपर्स और रियल एस्टेट क्षेत्र के दिग्गज भी शामिल होंगे, जो शहरी विकास को 'हरित स्वरूप' देने के लिए गहन विचार-मंथन करेंगे।

12 राशिफल में देखें अपना दिन

मेष मानसिक शांति के लिए किए गए प्रयास सफल रहेंगे। कोर्ट-कचहरी के कार्य मनोनुकूल रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। नौकरी में सहकर्मी साथ देंगे। प्रसन्नता रहेगी। किसी धार्मिक यात्रा की योजना बनेगी। पूजा-पाठ में मन लगेगा।

वृष वाहन व मशीनरी इत्यादि के प्रयोग में लापरवाही न करें। वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करें। अपेक्षित कार्यों में विलंब होगा। चिंता तथा तनाव रहेंगे। व्यापार ठीक चलेगा।

मिथुन कार्यक्षेत्र के लिए नई योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। बिगड़े काम बन सकते हैं। समाजसेवा करने का मन बनेगा। घर-बाहर पूछ-परख रहेगी। धन प्राप्ति सुगम होगी। व्यस्तता रहेगी। आराम का समय नहीं मिलेगा। थकान रहेगी।

कर्क व्यावसायिक यात्रा मनोनुकूल रहेगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग व मार्गदर्शन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यापार-व्यवसाय अच्छा चलेगा। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। बकाया वसूली के प्रयास सफल

सिंह समाजसेवा करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। मान-सम्मान मिलेगा। खोई हुई वस्तु मिलने के योग हैं। व्यापार-व्यवसाय अच्छा चलेगा। नौकरी में उच्चाधिकारी की प्रसन्नता प्राप्त होगी। शत्रु सक्रिय रहेंगे। जोखिम व जमानत के कार्य बिलकुल न करें।

कन्या शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कारोबार अच्छा चलेगा। नौकरी में सहकर्मी साथ देंगे। चिंता तथा तनाव रहेंगे। प्रतिद्वंद्विता में वृद्धि होगी। किसी आनंदोत्सव में भाग ले सकते हैं। भूले-बिसरे साथियों से मुलाकात होगी।

तुला किसी तरह से बड़ा लाभ होने की संभावना है। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे। किसी तरह के विवाद में विजय प्राप्त होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। नौकरी में नया कार्य मिल सकता है।

वृश्चिक कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। थकान व कमजोरी रह सकती है। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। कर्ज लेना पड़ सकता है। दूसरों से अधिक अपेक्षा न करें। बेवजह चिड़चिड़ापन रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। कार्य में मन नहीं लगेगा।

धनु भावना में बहकर महत्वपूर्ण निर्णय न लें। नौकरी में कार्यभार रहेगा। लाभ होगा। स्वास्थ्य के संबंध में लापरवाही न करें। स्वास्थ्य पर व्यय होगा। दु:खद समाचार मिल सकता है। क्रोध व उत्तेजना पर नियंत्रण रखें। कुसंगति से हानि होगी।

मकर मनपसंद व्यंजनों का आनंद प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग अपने कार्य उत्साह व लगन से कर पाएगा। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है। धन प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। व्यापार-व्यवसाय अच्छा चलेगा। प्रमाद न करें।

कुंभ घर, दुकान, फैक्टरी व शोरूम इत्यादि के खरीद-फरोख्त की योजना बनेगी। कारोबार में बड़ा लाभ हो सकता है। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। रुके काम बनेंगे। घर-बाहर उत्साह व प्रसन्नता से काम कर पाएंगे।

मीन प्रसन्नता का वातावरण निर्मित होगा। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा। कानूनी अड़चन दूर होकर स्थिति अनुकूल बनेगी। व्यापार-व्यवसाय अच्छा चलेगा। निवेश शुभ रहेगा। नौकरी में मातहत साथ देंगे।

विश्व व्यवस्था, भारत की दिशा और भविष्य की घटनाओं पर गहरा प्रभाव

प्रियंका जैन

वैदिक ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा, साहस, युद्ध, तकनीकी शक्ति और क्रियाशीलता का ग्रह माना जाता है। जब यह ग्रह किसी राशि में प्रवेश करता है, तो उस राशि के तत्व और स्वामी के अनुसार विशेष परिणाम उत्पन्न होते हैं। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है और इसका स्वामी शनि है, जो अनुशासन, व्यवस्था, कर्म और सामाजिक संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल और शनि का संबंध ज्योतिष में जटिल माना जाता है, क्योंकि मंगल त्वरित क्रिया और आक्रामक ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि शनि धीमी गति, धैर्य और नियंत्रण का प्रतीक है। जब तेज और उग्र ऊर्जा वाला मंगल अनुशासित और संरचनात्मक कुंभ राशि में प्रवेश करता है, तो यह स्थिति विश्व, समाज और राष्ट्रों के स्तर पर गहरे और दूरगामी परिवर्तन का संकेत देती है।

इस गोचर का सबसे प्रमुख प्रभाव वैश्विक स्तर पर तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है। कुंभ राशि नवाचार, आधुनिक तकनीक, अंतरिक्ष अनुसंधान और डिजिटल क्रांति की राशि मानी जाती है। मंगल की ऊर्जा जब इस क्षेत्र में सक्रिय होती है, तो नई खोज, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और वैज्ञानिक उपलब्धियों में तेजी आती है। दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र अंतरिक्ष मिशनों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और रक्षा तकनीक में तेजी से निवेश कर सकते हैं। नई ऊर्जा तकनीकों जैसे सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन ईंधन और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों में महत्वपूर्ण प्रगति संभव है। यह समय तकनीकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने वाला और मानव सभ्यता को नई दिशा देने वाला हो सकता है।

सामाजिक स्तर पर भी यह गोचर गहरे प्रभाव डालता है। कुंभ राशि जनसमूह, सामाजिक व्यवस्था और सामूहिक चेतना की राशि है। मंगल संघर्ष और क्रांति का प्रतीक है। जब ये दोनों ऊर्जा एक साथ आती हैं, तो दुनिया के विभिन्न देशों में जन आंदोलनों, विरोध प्रदर्शनों और सामाजिक परिवर्तन की लहर उठ सकती है। लोग अपने अधिकारों के लिए अधिक मुखर हो सकते हैं और पुरानी व्यवस्थाओं को चुनौती दे सकते हैं। कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता परिवर्तन या नई विचारधाराओं का उदय संभव है। यह समय समाज में जागरूकता और परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज करने वाला हो सकता है।

वायु तत्व से संबंधित क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। कुंभ वायु तत्व की राशि है और मंगल अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह संयोजन अचानक और अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत देता है। वैश्विक स्तर पर विमानन क्षेत्र में नई तकनीक का विकास हो सकता है, लेकिन साथ ही सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय बन सकता है, क्योंकि मंगल आक्रामक ऊर्जा का प्रतीक है और कुंभ डिजिटल नेटवर्क और संचार का प्रतिनिधित्व करता है। इस दौरान साइबर हमले, डेटा लीक या डिजिटल युद्ध जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं, जिससे देशों को अपनी साइबर सुरक्षा मजबूत करने की आवश्यकता महसूस होगी।

भारत के संदर्भ में यह गोचर विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। भारत एक तेजी से उभरती हुई तकनीकी और आर्थिक शक्ति है, और कुंभ राशि का संबंध नवाचार और विकास से है। मंगल की ऊर्जा भारत में बुनियादी ढांचे, रक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में तेजी ला सकती है। सरकार द्वारा डिजिटल परियोजनाओं, स्मार्ट सिटी, रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष अनुसंधान में नए कदम उठाए जा सकते हैं।

न्यूज़ ब्रीफ

पूर्व IAS गणेशशंकर मिश्र बने राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी गणेश शंकर मिश्रा को राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ़ का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति को लेकर योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की ओर से बुधवार देर शाम आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार, गणेश शंकर मिश्रा का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगा और आगामी निर्देश जारी होने तक वे इस पद पर बने रहेंगे।

धान खरीद को लेकर विपक्ष का सदन में हंगामा

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन धान खरीदी का मुद्दा सदन में जोरदार तरीके से उठा। कांग्रेस ने शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव लाकर आरोप लगाया कि कई किसान, विशेषकर एससी-एसटी वर्ग के, अब तक अपना धान नहीं बेच पाए हैं और सरकार जानबूझकर खरीदी सीमित कर रही है। प्रस्ताव अग्राह्य होने पर विपक्षी विधायकों ने हंगामा किया, कुछ सदस्य गर्भगृह तक पहुंच गए और उन्हें निलंबित कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस ने पूरे दिन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। विपक्ष ने मांग की कि या तो शेष धान की खरीदी दोबारा शुरू की जाए या प्रभावित किसानों की कर्जमाफी की जाए।

मुख्यमंत्री से मिले पूर्व क्रिकेटर कपिल देव

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से गुरुवार को नया रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान राज्य में खेलों के विस्तार, आधुनिक खेल अधोसंरचना, अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और उभरती प्रतिभाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कपिल देव का पारंपरिक स्मृति-चिह्न और 'पुण्यभूमि छत्तीसगढ़' कॉफी टेबल बुक भेंट कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए आधारभूत ढांचे और प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। कपिल देव ने भी राज्य में बन रहे सकारात्मक माहौल की सराहना करते हुए हैं।

बजट सत्र में CAG Report पेशः सब्सिडी और फिटनेस सर्टिफिकेट में भारी अनियमितता

बिहार पर 4,844 करोड़ का बकाया

एजेंसी । पटना

बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट सदन में रखी गई। रिपोर्ट में राज्य की आय, राजस्व वसूली और विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणियां दर्ज की गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल प्राप्तियां 1,72,688.02 करोड़ रुपये रहीं। इसमें से 48,152.63 करोड़ रुपये राज्य के अपने स्रोतों से अर्जित हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9,313.75 करोड़ (23.98%) अधिक हैं।

4,844 करोड़ का राजस्व बकाया

31 मार्च 2023 तक राज्य पर कुल 4,844 करोड़ रुपये का राजस्व बकाया पाया गया। इनमें से 1,430 .32 करोड़ रुपये पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। कई विभागों ने पुराने बकायों का समुचित विवरण उपलब्ध नहीं कराया, जिससे वसूली की प्रगति पर प्रश्नचिह्न लगा है। खनन, परिवहन, मद्य निषेध और भू-राजस्व से जुड़े विभागों द्वारा पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित बकायों का अद्यतन विवरण न देना रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेखित है।

कृषि सब्सिडी में गंभीर गड़बड़ियां

कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के क्रियान्वयन में व्यापक अनियमितताएं सामने आई हैं। वर्ष 2019 में 10 ऐसे जिलों में 21.48 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की गई, जिन्हें आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं किया था। इसी प्रकार 14 अन्य जिलों के आवेदकों को 4 .03 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जबकि वे चिन्हित आपदा क्षेत्र में शामिल नहीं थे। रबी और खरीफ सत्र 2019-20 के दौरान 151.92 करोड़ रुपये की सब्सिडी चिन्हित फसल क्षति क्षेत्र से 1.34 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में वितरित की गई।

159.28 करोड़ फर्जी मुआवजा भी बांटा

एसडीआरएफ मानकों के अनुरूप सहायता दरों का पालन नहीं होने से 3 .74 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ। डाटाबेस प्रबंधन और स्वीकृति प्रक्रिया में व्यावसायिक नियमों की अनदेखी के कारण 15 .53 लाख मामलों में 56 .14 करोड़ रुपये का अधिक, कम अथवा अनियमित भुगतान दर्ज किया गया। वहीं 2019-22 के बीच 6,81,617 मामलों में 159 .28 करोड़ रुपये की सब्सिडी ऐसे किसानों को दी गई, जहां फसल क्षति 33 प्रतिशत से कम थी।

अपराधों के खुलासे में विफलता

सिर्फ हत्याकांड ही नहीं, बल्कि क्षेत्र में हुई अन्य बड़ी वारदातों को सुलझाने में भी स्वाट टीम फिसड्डी साबित हुई। हाल ही में पयागपुर में एक ई-रिक्शा सवार महिला से 20 लाख रुपये के जेवर की टप्पेबाजी की घटना हुई थी। इसके अलावा, ननके नामक युवक की हत्या और इलाके में हुई कई बड़ी चोरियों के मामलों में भी टीम के हाथ अब तक खाली हैं। इन विफलताओं ने एसपी के धैर्य को जवाब दे दिया।

- माल एवं यात्रियों पर कर : 248 .58 करोड़ रुपये
- खनन एवं धातुकर्म उद्योग : 1,505 .16 करोड़ रुपये
- वाहन कर : 183 .39 करोड़ रुपये
- भू-राजस्व : 302 .47 करोड़ रुपये
- मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क : 215 .61 करोड़ रुपये
- राज्य उत्पाद (एक्साइज) : 54 .30 करोड़ रुपये
- वस्तु एवं सेवा कर : 3 .25 करोड़ रुपये
- विद्युत कर एवं शुल्क : 20 लाख रुपये

सवालों के घेरे में फिटनेस प्रमाणपत्र

परिवहन विभाग में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किए बिना वाहनों को फिटनेस प्रमाणपत्र जारी किए गए, जिससे 2 .27 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई। रिपोर्ट के अनुसार 47,223 वाहनों में से 42,672 (90 प्रतिशत से अधिक) को प्रावधानों के उल्लंघन के बावजूद फिटनेस प्रमाणपत्र दिए गए।

सूर्योदय होते ही छापा मारने पहुंचा अफसरों का काफिला

- पांचजन्य प्लाई बोर्ड फैक्ट्री के कई ठिकानों पर आईटी की रेड

एजेंसी । पटना

बरेली। उत्तर प्रदेश के फरीदपुर क्षेत्र स्थित भगवानपुर फुलवा गांव में संचालित पांचजन्य प्लाई बोर्ड फैक्टरी पर गुरुवार तड़के आयकर विभाग ने व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। सुबह करीब पांच बजे अधिकारियों का काफिला फैक्टरी परिसर में पहुंचा और प्रवेश के साथ ही वित्तीय अभिलेखों की जांच प्रारंभ कर दी गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से औद्योगिक क्षेत्र में हलचल मच गई।

यूपी से उत्तराखंड तक फैली जांच

सूत्रों के अनुसार, करीब दस टीमों ने एक साथ फैक्टरी मालिक रवि नोमानी के आवास और उनसे जुड़े अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी छापेमारी की। जांच का दायरा उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड तक विस्तारित बताया जा रहा है। टैक्स अनियमितताओं की आशंका के मद्देनज़र यह समन्वित कार्रवाई की गई है।

सुरक्षा घेरा और उत्पादन ठप

कार्रवाई के दौरान फैक्टरी परिसर के बाहर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई और बाहरी आवाजाही सीमित कर दी गई। सुबह की पाली में पहुंचे मजदूरों को प्रबंधन की ओर से वापस लौटा दिया गया, जिससे उत्पादन पूरी तरह ठप रहा। सुरक्षा कर्मियों ने स्पष्ट किया कि प्रवेश पर रोक प्रबंधन स्तर से लगाई गई थी।

उद्योग जगत में बढ़ी हलचल

इस हाई-प्रोफाइल छापेमारी से क्षेत्र के व्यापारिक समुदाय में चिंता का माहौल है। प्लाई बोर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष शेखर अग्रवाल ने कहा कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने जोड़ा कि यदि कहीं अनियमितता पाई जाती है तो कानून के तहत कार्रवाई हो, लेकिन वैध कारोबार प्रभावित नहीं होना चाहिए। फिलहाल आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है और उद्योग जगत की निगाहें जांच के निष्कर्षों पर टिकी हैं।विभागीय अधिकारी खातों, डिजिटल डाटा और दस्तावेजों की गहन पड़ताल में जुटे हैं, जबकि आधिकारिक तौर पर अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ को बम से उड़ाने की धमकी

- मोबाइल पर आया एसएमएस, कचहरी परिसर में भी विस्फोट की चेतावनी

- सूचना मिलते ही वाराणसी पुलिस ने चलाया व्यापक तलाशी अभियान

एजेंसी । वाराणसी

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कचहरी परिसर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं।

पूरे परिसर की हुई तलाशी

सिटी मजिस्ट्रेट, एसीपी कैंट और स्थानीय पुलिस बल के साथ बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड ने पूरे न्यायालय परिसर की तलाशी ली। जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई, हालांकि एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

अज्ञात पर मुकदमा दर्ज

वाराणसी कमिश्नरेट के संयुक्त पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और धमकी भेजने वाले की पहचान के लिए तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है।

पत्नी-बच्चों की हत्या का आरोपी 23 साल बाद बरी

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पत्नी और तीन बच्चों की हत्या के आरोप में करीब 23 वर्ष से जेल में बंद एक व्यक्ति को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा।

दस मार्च तक अपलोड कराएं संपत्तियों का ब्यौरा

- योगी सरकार ने सूबे के 47 हजार कर्मियों को एक और मौका

एजेंसी । लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का विवरण दर्ज न करने वाले 47,816 अधिकारियों और कर्मचारियों को अंतिम अवसर दिया है। मुख्य सचिव S. P. Goyal के निर्देशानुसार संबंधित कार्मिक 26 फरवरी से 10 मार्च तक अपना विवरण अपलोड कर सकते हैं।

शासन ने स्पष्ट किया है कि 31 जनवरी तक विवरण न भरने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि निर्धारित तिथि तक जानकारी अपलोड न करने वाले कर्मचारियों को पदोन्नति, एसीपी, विदेश यात्रा तथा प्रतिनियुक्ति के लिए विजिलेंस क्लीयरेंस से वंचित रखा जाएगा।

सत्यापन के बाद मिलेगा वेतन

जनवरी का वेतन रोकने और संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी की जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि जो कर्मचारी 10 मार्च तक संपत्ति विवरण अपलोड कर देंगे, उन्हें सत्यापन के बाद जनवरी और फरवरी 2026 का वेतन जारी कर दिया जाएगा।

व्यापार जगत

एजीआर और रेवेन्यू शेयर में जियो अव्वल

- 43% हिस्सेदारी के साथ मजबूत बढ़त

मुंबई। टेलीकॉम सेक्टर पर ICICI सिक्योरिटीज और CLSA की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, रिलायंस जियो ने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही (Q3FY26) में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी बाजार हिस्सेदारी को 43% तक पहुँचा दिया है। इस अवधि के दौरान कंपनी का एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) 321 अरब रहा, जो सालाना आधार पर 11.2% की दमदार वृद्धि दर्शाता है। रिपोर्ट बताती है कि पूरी इंडस्ट्री का कुल AGR 720 अरब रहा, जिसमें जियो ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारती एयरटेल (299 अरब) पर स्पष्ट बढ़त बना ली है।

16 टेलीकॉम सर्किलों और मेट्रो शहरों में मजबूत पकड़

सर्किल स्तर के आंकड़ों पर गौर करें तो रिलायंस जियो ने देश के 22 में से 16 टेलीकॉम सर्किलों में अपनी पकड़ और मजबूत की है। विशेष रूप से गुजरात, यूपी ईस्ट, यूपी वेस्ट, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में कंपनी के रेवेन्यू शेयर में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे प्रमुख मेट्रो मार्केट में भी जियो की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है, जो इसके नेटवर्क विस्तार और बेहतर ग्राहक जुड़ाव की रणनीति को सफल साबित करता है।

प्रतिस्पर्धियों के बीच बढ़त और भविष्य की रणनीति

CLSA की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 12 महीनों में जहाँ जियो और एयरटेल ने अपनी बाजार हिस्सेदारी में सुधार किया है, वहीं वोडाफोन आइडिया की हिस्सेदारी गिरकर लगभग 13% पर सिमट गई है। जियो ने तिमाही आधार पर 41 बेसिस पॉइंट और सालाना आधार पर 114 बेसिस पॉइंट की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाकर अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति को और सुदृढ़ किया है। वर्तमान में कंपनी का पूरा ध्यान रेवेन्यू ग्रोथ, सर्किल-स्तरीय विस्तार और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से बाजार में अपनी नंबर-1 की स्थिति को बरकरार रखने पर केंद्रित है।

WTO: जुलाई में होगी ट्रेड पॉलिसी की समीक्षा

एजेंसी । नई दिल्ली

वैश्विक व्यापार ढांचे में भारत की नीतिगत दिशा की पड़ताल अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर होगी। World Trade Organization (डब्ल्यूटीओ) जुलाई 2026 में भारत की आठवीं व्यापार नीति समीक्षा (Trade Policy Review) आयोजित करेगा। इस प्रक्रिया में सदस्य देश भारत की टैरिफ संरचना, व्यापार सुगमता उपायों, सब्सिडी ढांचे और नियामकीय सुधारों का व्यापक आकलन करेंगे। वित्त मंत्रालय के अनुसार, निर्धारित समीक्षा से पहले भारत ने जिनेवा में डब्ल्यूटीओ के समक्ष सीमा-शुल्क आधुनिकीकरण और डिजिटल सुधारों पर विस्तृत प्रस्तुति दी है।

टीएफए प्लस' उपायों की दिशा में बढे.कदम

'24 फरवरी को भारत के स्थायी मिशन और सीबीआईसी द्वारा डब्ल्यूटीओ मुख्यालय में विशेष व्यापार सुगमता सत्र आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 40 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मंत्रालय ने बताया कि भारत ने टीएफए के तहत अपनी 100 प्रतिशत अधिसूचनात्मक प्रतिबद्धताओं को समय-सीमा के भीतर पूरा कर लिया है। अब देश 'टीएफए प्लस' उपायों की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो राष्ट्रीय व्यापार सुगमता कार्ययोजना (NTFAP 3.0) के तहत न्यूनतम मानकों से आगे जाकर वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर केंद्रित हैं।

एनएमडीसी और आईआईटी हैदराबाद ने मिलाया हाथ

- खनन क्षेत्र में उद्योग-अकादमिक गठजोड़ से बढ़ेगा नवाचा

नई दिल्ली। देश के खनिज और धातु क्षेत्र में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन को गति देने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र की खनन कंपनी NMDC Limited ने हैदराबाद स्थित Indian Institute of Technology Hyderabad के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह करार अनुसंधान, नवाचार और स्वदेशी तकनीकी विकास को संस्थागत रूप देने की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है।

खनिज प्रसंस्करण से हरित इस्पात तक

दोनों संस्थान लौह अयस्क बेनीफिशिएशन और एग्लोमेरेशन तकनीकों, हरित इस्पात निर्माण प्रक्रियाओं तथा स्वदेशी कच्चे माल पर आधारित वैकल्पिक आयरन-मेकिंग तकनीकों पर संयुक्त अनुसंधान करेंगे। उन्नत मॉडलिंग और सिमुलेशन के माध्यम से खनन-धातुकर्म प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाने पर भी काम होगा।

डिजिटल माइनिंग और माइनिंग 4.0

एमओयू के तहत स्वायत्त वाहन संचालन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), ड्रोन आधारित सर्वेक्षण और 'माइनिंग 4.0' ढांचे पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। इन पहलों का लक्ष्य परिचालन लागत में कमी, उत्पादकता में वृद्धि और पर्यावरणीय अनुपालन को बेहतर बनाना है।

नवाचार को संस्थागत समर्थन

एनएमडीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अमिताभ मुखर्जी ने कहा कि यह उद्योग-अकादमिक सहयोग कंपनी की अनुसंधान क्षमता को नई दिशा देगा। उनके अनुसार, आईआईटी हैदराबाद की अकादमिक विशेषज्ञता और एनएमडीसी का फील्ड अनुभव मिलकर स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास को तेज करेंगे, जो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को मजबूती देगा।

एनएमडीसी के पूरे हो रहे 50 साल

गौरतलब है कि यह समझौता ऐसे समय हुआ है जब एनएमडीसी का अनुसंधान एवं विकास केंद्र खनिज क्षेत्र में योगदान के 50 वर्ष पूरे कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल खनन उद्योग में प्रौद्योगिकी-आधारित रूपांतरण और दीर्घकालिक सतत विकास के लिए एक संरचित मंच तैयार करेगी।

सोना हल्का मजबूत, चांदी में नरमी

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमतों में हल्की बढ़त दर्ज की गई, जबकि चांदी में मामूली गिरावट रही। 24 कैरेट सोना 100–110 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ, वहीं चांदी करीब 100 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हुई।

राजधानी New Delhi में 24 कैरेट सोना 1,62,050 रुपये और 22 कैरेट 1,48,560 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता रहा। Mumbai में 24 कैरेट 1,61,900 रुपये और 22 कैरेट 1,48,410 रुपये रहा। Ahmedabad, Chennai और Kolkata में भी भाव लगभग इसी दायरे में रहे। चांदी का भाव दिल्ली बाजार में 2,84,900 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया।

अन्य प्रमुख शहरों लखनऊ, जयपुर, पटना, बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में भी सोने के दाम समान रुझान के साथ कारोबार करते दिखे। कुल मिलाकर, बाजार सीमित दायरे में स्थिर रहा, जिसमें सोने ने हल्की मजबूती दिखाई जबकि चांदी की चमक फीकी पड़ी।

अंतिम चार पर न्यूजीलैंड की निगाह

- एक और जीत न्यूजीलैंड को दिलाएगी सेमीफाइनल का टिकट, इंग्लैंड से टक्कर
- 7 बार विश्व कप में दोनों टकराए हैं इंग्लैंड ने चार और न्यूजीलैंड ने तीन जीत दर्ज की है

एजेंसी । कोलंबो

न्यूजीलैंड की टीम इस समय ग्रुप में सबसे मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। श्रीलंका के खिलाफ पिछले मैच में मिली शानदार जीत ने कीवी टीम के हौसले बुलंद कर दिए हैं। शुक्रवार को इंग्लैंड के खिलाफ जीत दर्ज करते ही न्यूजीलैंड आधिकारिक रूप से सेमीफाइनल का टिकट कटा लेगा। टीम की संतुलित बल्लेबाजी और घातक स्पिन आक्रमण उन्हें इस मुकाबले में प्रबल दावेदार बना रहा है।

इंग्लैंड के लिए साख और लय की लड़ाई

हालांकि इंग्लैंड की टीम पहले ही अंतिम चार (सेमीफाइनल) में जगह पक्की कर चुकी है, लेकिन उनके लिए यह मैच लय हासिल करने का आखिरी मौका है। टूर्नामेंट में अब तक अंग्रेज बल्लेबाज संघर्ष करते दिखे हैं। सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले से पहले इंग्लैंड चाहेगा कि उनके शीर्ष क्रम के बल्लेबाज रन बनाएं और टीम ग्रुप में शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाकर अगले दौर में प्रवेश करे।

स्पिनरों की अग्निपरीक्षा और कीवी रणनीति

न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ छह स्पिनरों को उतारकर सबको चौंका दिया था, जिन्होंने मिलकर 17 ओवर फेंके। पल्लेकेले के बाद अब प्रेमदासा की 'चिपचिपी' पिच पर मिचेल सैंटनर, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स और कोल की चौकड़ी इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए काल साबित हो सकती है। कीवी टीम का यह स्पिन जाल ही मैच का रुख तय करेगा।

रन रेट का गणित और पाकिस्तान की उम्मीदें

ग्रुप के समीकरण काफी दिलचस्प हैं। न्यूजीलैंड का नेट रन रेट +3.050 है, जबकि इंग्लैंड से हार के बाद पाकिस्तान का रन रेट -0.461 पर गिर गया है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए न केवल श्रीलंका को बड़े अंतर से हराना होगा, बल्कि यह दुआ भी करनी होगी कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को एक तरफा मुकाबले में करारी शिकस्त दे।

आमने-सामने

कुल मैच	: 30
न्यूजीलैंड जीता	: 10
इंग्लैंड जीता	: 17
बेनतीजा	: 03

हैरी ब्रूक बनाम कीवी स्पिन आक्रमण

इंग्लैंड के लिए सबसे सकारात्मक पहलू हैरी ब्रूक की फॉर्म है। पाकिस्तान के खिलाफ शतक जड़ने वाले ब्रूक ने स्पिनरों को खेलने की अपनी काबिलियत साबित की है।

महिला टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया से सीरीज बचाने की चुनौती

- 62 मैच दोनों टीमें ने अब तक आपस में खेले हैं
- 50 में ऑस्ट्रेलिया और 12 में भारतीय टीम जीती

एजेंसी । होबार्ट

मौजूदा विश्व चैंपियन भारतीय महिला टीम शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया से दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भिड़ेगी। पहले मैच में बुरी तरह हारने के बाद wअब मेहमान टीम के सामने तीन मैचों की सीरीज बचाने की चुनौती होगी। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया से कभी द्विपक्षीय सीरीज नहीं जीती है।

वापसी की उम्मीद

भारत को शुक्रवार को इन चारों से वापसी करते हुए अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। बड़े शॉट लगाने में माहिर विकेटकीपर ऋचा घोष को भी संघर्ष करना पड़ा और वह केवल 23 रन ही बना सकी। टीम को उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। गेंदबाजों में बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी ने दो विकेट लिए लेकिन उन्हें बीच के ओवरों में दीप्ति शर्मा और कासवी जैसी गेंदबाजों से मदद की जरूरत है। शुरुआती ओवरों में विरोधी टीम को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी तेज गेंदबाज रेणुका सिंह और क्रांति गौड़ पर होगी, जो पहले मैच में असफल रहीं। प्रबंधन ऑलराउंडर अमनजोत कौर और स्नेह राणा को टीम में शामिल कर सकता है।

हमने एक टीम के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन परिणाम हमारे अनुकूल नहीं रहा। हम अगले मैच में मजबूत वापसी करेंगे। हम इसके बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हैं और अपने मजबूत पक्षों पर ध्यान लगा रहे हैं।

-दीप्ति शर्मा, भारतीय ऑलराउंडर

सभी 11 सीरीज गंवाई

टी-20 सीरीज 2-1 से जीतने के बाद भारतीय टीम वनडे सीरीज की अच्छी शुरुआत नहीं कर पाई और पहला मैच छह विकेट से हार गई। इस प्रारूप में इन दोनों देशों के बीच अभी तक 11 द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेली गई हैं, सभी ऑस्ट्रेलिया ने जीतीं। लेकिन भारत 2025 में महिला वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर मिली पांच विकेट की जीत से प्रेरणा लेने की कोशिश करेगा। पहले मैच में भारतीय टीम 214 रन पर आउट हो गई थी। उप-कप्तान स्मृति मंधाना (58), कप्तान हरमनप्रीत कौर (53) और कासवी गौतम (43) को छोड़कर कोई भी अन्य भारतीय बल्लेबाज बड़ी पारियां नहीं खेल सकीं। प्रतिका रावल खाता भी नहीं खोल पाईं। शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरीं।

शानदार विदाई पर नजर

ऑस्ट्रेलिया की निगाह दूसरे मैच में ही सीरीज अपने नाम करके कप्तान एलिसा हीली को शानदार विदाई देने पर होगी। हीली अपनी आखिरी अंतरराष्ट्रीय सीरीज में खेल रही हैं। उन्होंने पिछले मैच में अर्धशतक लगाया था। हीली और फोबे लिचफील्ड ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की। वे इस लय को जारी रखना चाहेंगी। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी भी शानदार रही है।

बाहर होने के बाद शनाका ने देशवासियों से मांगी माफी

कोलंबो। श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने बुधवार को विश्व कप से बाहर होने के बाद देशवासियों से माफी मांगी और कहा कि वे उन्हें खुशी देने में असफल रहे। टीम न्यूजीलैंड से 61 रन से हार गई थी। यह उसकी लगातार दूसरी पराजय है। अब पाकिस्तान के खिलाफ उसका आखिरी मैच औपचारिक रह गया है। शनाका ने मैच के कहा, हमें इसका बहुत अफसोस है। इंग्लैंड के खिलाफ मैच भी ऐसा ही था जिसे हम जीत सकते थे। अगर हम थोड़ा और समझदारी से खेलते तो वह मैच भी जीत सकते थे। यह मैच एकतरफा था। प्रशंसकों के लिए मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। हमने उन्हें ऐसी कोई जीत नहीं दी जिस पर वे खुश हो सकें।

'सरकार करे हस्तक्षेप'

उन्होंने कहा कि उनकी टीम के बाहर होने के लिए केवल फिटनेस और फॉर्म ही एकमात्र कारण नहीं थे, बल्कि इसके लिए 'बाहर का नकारात्मक माहौल' भी जिम्मेदार रहा। इसके अलावा उन्होंने सरकार से खिलाड़ियों को आलोचना से बचाने के लिए हस्तक्षेप करने की अजीबोगरीब मांग की। शनाका ने कहा, खिलाड़ी होने के कारण हमारे लिए बाहर हो रही बातों को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। हम अधिकतर समय नकारात्मक बातें ही सुनते हैं।

सितारों से सजी कर्नाटक की टीम पर फॉलोऑन का संकट

जम्मू-कश्मीर खिताब की ओर बढ़ी

- पहली पारी में 584 रन बनाने के बाद मेजबान टीम के शीर्ष क्रम को किया ध्वस्त
- 58 विकेट नबी पूरे सत्र में ले चुके हैं जो उत्तराखंड के मयंक मिश्रा से सिर्फ एक कम है
- 05 विकेट पर कर्नाटक ने 220 रन बनाए, फॉलोऑन टालने के लिए 165 रन और चाहिए

रणजी ट्रॉफी

हुबली। सितारों से सजी आठ बार की रणजी चैंपियन कर्नाटक की टीम जम्मू-कश्मीर के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में फॉलोऑन की दहलीज पर पहुंच गई है। जम्मू-कश्मीर ने तेज गेंदबाज आकिब नबी की धारदार गेंदबाजी से मेजबान टीम के शीर्ष क्रम को ध्वस्त करते हुए पहला ऐतिहासिक रणजी खिताब जीतने की ओर कदम बढ़ा दिए। रणजी में 1959-60 में पदार्पण करने के बाद जम्मू-कश्मीर की टीम पहली बार फाइनल में पहुंची है। मैच के तीसरे दिन गुरुवार को मेजबान टीम ने मयंक अग्रवाल के संघर्षपूर्ण नाबाद 130 रन की मदद से पहली पारी में पांच विकेट पर 220 रन बनाए थे। दिन का खेल खत्म होने के समय उनके साथ दूसरे छोर पर क्रुतिक कृष्णा 27 रन पर मौजूद थे। दोनों छठे विकेट के लिए 58 रन की नाबाद साझेदारी कर चुके थे। इससे पहले जम्मू-कश्मीर ने पहली पारी में 584 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। कर्नाटक पहली पारी के आधार पर 364 रन से पीछे है और फॉलोऑन से बचने के लिए उसे 165 रन और चाहिए।

साउथ अफ्रीका ने बढ़ाए सेमीफाइनल की ओर कदम

- वेस्टइंडीज की हार ने टीम इंडिया से हटाया नेट रनरेट का साया

एजेंसी । अहमदाबाद

एडेन मार्करम की अगुवाई वाली साउथ अफ्रीकी टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सेमीफाइनल की सीट पक्की करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। भारत को 76 रनों से हारने के बाद साउथ अफ्रीका ने गुरुवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में 9 विकेट से धमाकेदार जीत हासिल की। वेस्टइंडीज ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 177 रनों का टारगेट दिया, जिसे साउथ अफ्रीका ने 16.1 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर चेज किया। ग्रुप-1 का हिस्सा साउथ अफ्रीका के खाते में दो मैचों में चार अंक हो गए हैं और तालिका में शीर्ष पर काबिज हो गई है। वेस्टइंडीज के दो मैचों में दो अंक हैं। वेस्टइंडीज की हार से टीम इंडिया के सिर से नेट रनरेट का साया हट गया है। डिफेंडिंग चैंपियन भारत को अब दो सुपर-8 मैचों में सिर्फ जीत हासिल करने होगी और उसकी सेमीफाइनल में एंट्री हो जाएगी।

वेस्टइंडीज ने 60 के अंदर गंवाए 5 विकेट

इससे पहले, वेस्टइंडीज ने निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट पर 176 रन जुटाए। वेस्टइंडीज ने शुरुआती झटकों के बाद निचले क्रम के बल्लेबाज रोमारियो शेफर्ड (नाबाद 52 रन) के अर्धशतक और जेसन होल्डर (49 रन) के साथ आठवें विकेट के लिए 89 रन की रिकॉर्ड साझेदारी से वापसी करते हुए चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया।

एडेन मार्करम प्लेयर ऑफ द मैच बने

वेस्टइंडीज के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने कप्तान एडेन मार्करम की शानदार पारी के दम पर आसानी से लक्ष्य हासिल किया। मार्करम ने 46 गेंदों में नाबाद 82 रन बनाए। उनके बल्ले से सात चौके और चार छक्के लगाए। उन्होंने मौजूदा टूर्नामेंट में तीसरी बार पचास प्लस स्कोर बनाया। मार्करम ने क्विंटन डिकॉक के साथ पहले विकेट के लिए 95 रनों की दमदमरा साझेदारी की और वेस्टइंडीज को बैकफुट पर धकेल दिया। डिकॉक फिफ्टी से चूक गए। उन्होंने 24 गेंदों में 47 रन जुटाए, जिसमें चार चौके और चार सिक्स शामिल हैं। डिकॉक को रोस्टन चेस ने आठवें ओवर में आउट किया। इसके बाद मार्करम ने रयान रिकेल्टन के साथ 82 रनों की अटूट साझेदारी की और साउथ अफ्रीका को जीत की दहलीज पार कराई। रिकेल्टन ने 28 गेंदों में चार चौकों और दो छक्कों की मदद से नाबाद 45 रन बनाए।

बॉलीवुड

बेटी के जन्म को याद कर भावुक हुईं प्रियंका

प्रियंका चोपड़ा ने अपने अभिनय से बॉलीवुड के साथ-साथ हॉलीवुड में भी खास पहचान बनाई है। उनकी हालिया रिलीज 'द ब्लफ' में उनका अलग अंदाज देखने को मिला। इसी बीच एक्ट्रेस ने मातृत्व से जुड़े अपने निजी अनुभव शेयर किए हैं, जो भावुक कर देने वाले हैं। जनवरी 2022 में प्रियंका और उनके पति निक जोनस सरोगेसी के जरिए बेटी के माता-पिता बने। उन्होंने अपनी बेटी का नाम मालती मैरी चोपड़ा जोनस रखा। हाल ही में एक पॉडकास्ट में प्रियंका ने बताया कि मालती का जन्म प्रीमेच्योर हुआ था, जिसके कारण उसे एनआईसीयू में भर्ती करना पड़ा। एक्ट्रेस ने उस समय को याद करते हुए कहा कि शुरुआत में एक समय पर केवल एक ही व्यक्ति को बच्ची से मिलने की अनुमति थी। उन्होंने बताया कि जब उनकी बेटी पहली बार रोई तो उसकी आवाज बिल्ली जैसी लगी, जो उनके लिए बेहद भावुक क्षण था। प्रियंका ने खुलासा किया कि उस कठिन दौर में परिवार उनके साथ खड़ा रहा, लेकिन मीडिया में खबर लीक होने की आशंका के कारण उन पर बेटी के जन्म की घोषणा करने का दबाव भी था। उन्होंने कहा कि वे उस समय मानसिक रूप से तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि बच्ची की सेहत कैसी रहेगी। एनआईसीयू में बिताए गए समय को याद करते हुए प्रियंका ने बताया कि निक जोनस अपनी बेटी के पास बैठकर गिटार बजाते और गाने सुनाते थे। वहीं वह खुद छोटे आईपॉड पर महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र और 'ओम नमः शिवाय' जैसे मंत्र चलाती थीं। प्रियंका के मुताबिक, उस कठिन समय में आध्यात्मिक तरीकों ने उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाए रखा। एक्ट्रेस के इस खुलासे ने एक बार फिर यह दिखाया है कि ग्लैमर की दुनिया के पीछे भी संघर्ष और संवेदनाएं छिपी होती हैं।

शादी के बंधन में बंधे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा

साउथ सिनेमा के चर्चित सितारे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अब आधिकारिक रूप से पति-पत्नी बन चुके हैं। दोनों ने 26 फरवरी को पारंपरिक तेलुगु रीति-रिवाजों के साथ विवाह संपन्न किया। उनकी शादी दो अलग-अलग परंपराओं के तहत आयोजित की जा रही है। पहली रस्म पूरी होने के साथ ही दोनों ने एक-दूसरे को जीवनसाथी के रूप में स्वीकार कर लिया है, जबकि शाम को परिवार की मौजूदगी में कोडवा परंपराओं के अनुसार दूसरी रस्म निभाई जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस शाही शादी को खास बनाने के लिए 'आदिम' थीम को अपनाया गया है, जिसमें पारंपरिक और प्राचीन भारतीय रीति-रिवाजों को प्राथमिकता दी गई है। यह थीम पुराने समय की सादगी और सांस्कृतिक गहराई को दर्शाती है। करीबी सूत्रों के मुताबिक, समारोह में सरल अनुष्ठानों, पारंपरिक सजावट और पुरानी विरासत की झलक देखने को मिल रही है, जो इसे आधुनिक शादियों से अलग बनाती है। इस भव्य शादी की रस्में 23 फरवरी से ही शुरू हुई थीं। शुरुआत एक खास डिनर पार्टी से हुई, जिसके बाद हल्दी, मेहंदी और संगीत समारोह की झलकियां सोशल मीडिया पर वायरल होती रहीं। दिलचस्प बात यह रही कि इस पूरे समारोह के दौरान कपल ने खुद भी फैंस के साथ अपनी खुशियों के पल शेयर किए, जिससे यह शादी लगातार चर्चा में बनी हुई है।

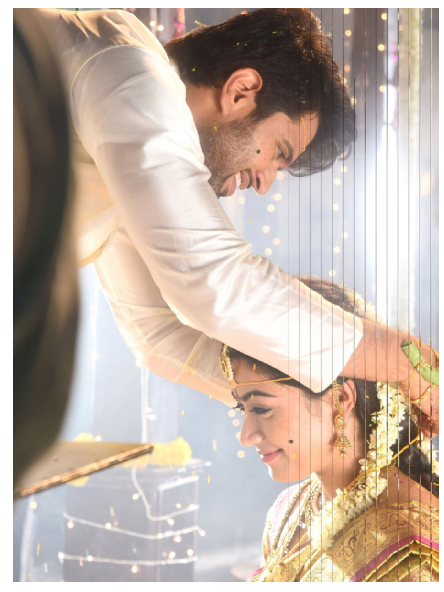

तमिलनाडु में यश का जलवा, 'टॉक्सिक' की रिकॉर्ड डील

तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस में बड़ा खेल हो गया है। रॉकिंग स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की तमिलनाडु डिस्ट्रीब्यूशन डील 63 करोड़ रुपये एडवांस पर कमीशन बेसिस में लॉक हो गई है। हाल के वर्षों में यह राज्य की सबसे बड़ी डील्स में से एक मानी जा रही है। ट्रेड सर्किल में इसे आने वाली सबसे बड़ी रिलीज में शुमार किया जा रहा है। पूरे तमिलनाडु में फिल्म को मल्टी-डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल के साथ रिलीज किया जाएगा। चेन्नई सिटी की जिम्मेदारी थिंक स्टूडियोज के स्वरूप रेड्डी संभालेंगे, जबकि चेंगलपट्टू एरिया व्हाइट नाइट्स के ट्राइडेंट रवि के पास रहेगा। कोयंबटूर, नॉर्थ और साउथ आर्कोट, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी सर्किट एस पिक्चर श्रीनिवासन देखेंगे।

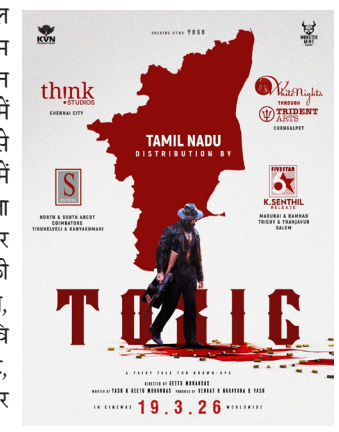

पारिवारिक विवाद की खबरों पर हेमा मालिनी ने तोड़ी चुप्पी

बॉलीवुड की 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के निधन के बाद परिवार में अनबन की खबरों पर चुप्पी तोड़ते हुए सभी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। हाल ही में अलग-अलग प्रार्थना सभाओं को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं, जिन पर प्रतिक्रिया देते हुए हेमा ने स्पष्ट कहा कि परिवार पूरी तरह एकजुट है और सभी सदस्य एक-दूसरे से गहरा लगाव रखते हैं। हेमा ने बातचीत में बताया कि धर्मेंद्र के लिए पूरा परिवार एक साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि चाहे उनकी बेटियां ईशा देओल और अहाना हों या फिर दूसरे परिवार के सदस्य सनी देओल और बॉबी देओल, सभी धर्मेंद्र से बेहद प्यार करते हैं और आपस में भी अच्छे संबंध शेयर करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जहां धर्मेंद्र जैसे व्यक्तित्व की छाया होती है, वहां नकारात्मकता की कोई जगह नहीं होती।

अरावली और मणिपुर मामले में 'सुप्रीम' सख्ती

- मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम और सख्त निर्देश जारी किए
- अरावली क्षेत्र की सही परिभाषा तय करने के मामले में बनेगा विशेषज्ञ पैनल
- सोनम वांगचुक की याचिका पर अंतिम सुनवाई तय

मणिपुर हिंसा

एजेंसी । नई दिल्ली

देश की शीर्ष अदालत ने गुरुवार को तीन अलग-अलग संवेदनशील मामलों में महत्वपूर्ण रुख अपनाया है। अरावली की सीमाओं को स्पष्ट करने के लिए विशेषज्ञ समिति की सुगबुगाहट से लेकर, मणिपुर हिंसा के पीड़ितों को न्याय प्रक्रिया में सीधे जोड़ने और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत पर अंतिम फैसले की तारीख तय करने तक—सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वह जवाबदेही और स्पष्टता को प्राथमिकता दे रहा है।

पीड़ितों को दी जाएगी चार्जशीट की कॉपी

मणिपुर में 2023 में हुई जातीय हिंसा से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम और सख्त निर्देश जारी किए। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसियां पीड़ितों और उनके परिवारों को अंधेरे में नहीं रख सकतीं। इसलिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और मणिपुर पुलिस की विशेष जांच टीमों को निर्देश दिया गया है कि जिन मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है, उसकी प्रतियां सीधे पीड़ितों और उनके परिवारों को उपलब्ध कराई जाएं। अदालत ने साफ किया कि न्याय प्रक्रिया में पीड़ितों की भागीदारी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश मणिपुर हिंसा मामलों की जांच की निगरानी कर रहे पूर्व महाराष्ट्र पुलिस प्रमुख दत्तात्रेय पडसलगीकर की 12वीं स्थिति रिपोर्ट देखने के बाद दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि सीबीआई अब तक 20 हिंसा मामलों में विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। वहीं छह अन्य एफआईआर की जांच जारी है और अगले छह महीने में उन्हें पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने जांच एजेंसियों को तय समय सीमा में बाकी मामलों की जांच पूरी करने के निर्देश भी दिए।

पीड़ितों को मिलेगा मुफ्त कानूनी सहारा

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने अदालत को बताया कि कई पीड़ितों और उनके परिवारों को यह तक नहीं पता कि उनके मामलों में क्या कार्रवाई हुई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को हर पीड़ित को मुफ्त कानूनी सहायता देने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि ऐसे वकील नियुक्त किए जाएं जो स्थानीय भाषा जानते हों ताकि पीड़ित आसानी से अपनी बात रख सकें। अदालत ने यह भी कहा कि इन वकीलों के गुवाहाटी आने-जाने और ठहरने का खर्च मणिपुर विधिक सेवा प्राधिकरण उठाएगा।

अरावली क्षेत्र पर 'यथास्थिति' बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र की सही परिभाषा तय करने के मामले में अगली सुनवाई तय की है। कोर्ट एक विशेषज्ञ समिति बनाने पर विचार करेगा, जो यह देखेगी कि अरावली क्षेत्र की सीमा क्या हो और उससे जुड़े मुद्दों को कैसे सुलझाया जाए। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल जिन गतिविधियों, खासकर खनन के लिए लाइसेंस दिए गए थे, वे रुके रहेंगे।

बुकिंग के 48 घंटे के अंदर टिकट रद्द किया तो मिलेगा पूरा रिफंड

डीजीसीए ने एयरलाइन टिकट रिफंड नियमों में किया संशोधन

एजेंसी । नई दिल्ली

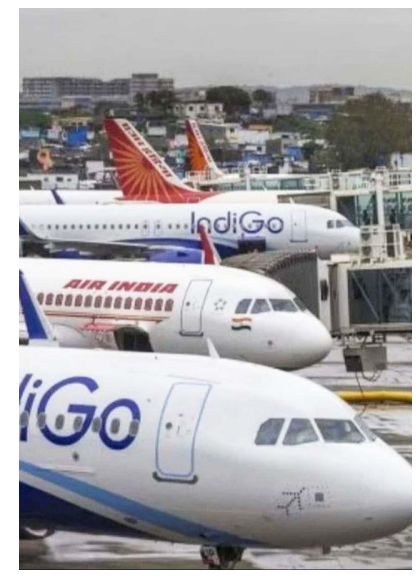

विमानन नियामक डीजीसीए ने एयरलाइन टिकट रिफंड नियमों में संशोधन किया है। अब यात्री हवाई टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या बदल सकते हैं, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हों। डीजीसीए ने यात्रियों के अनुकूल संशोधित नियम जारी किए हैं। इसके तहत एयरलाइन को यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि यात्री टिकट बुकिंग के 24 घंटे के भीतर अपने नाम में कोई गलती दिखाए और टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया हो, तो इसका कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

डीजीसीए ने क्या कहा?

डीजीसीए ने कहा, यदि टिकट ट्रैवल एजेंट या पोर्टल के माध्यम से खरीदी गई है, तो रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि हैं। एयरलाइन यह सुनिश्चित करें कि रिफंड प्रक्रिया 14 कार्यदिवसों के भीतर पूरी हो। इसके अलावा, यात्री या उसके परिवार के किसी सदस्य की चिकित्सा आपात स्थिति के कारण टिकट रद्द करने की शर्तों में भी बदलाव किए गए हैं। यह संशोधन इसलिए किया गया है, क्योंकि पिछले समय में यात्रियों की शिकायतें बढ़ रही थीं कि उन्हें समय पर रिफंड नहीं मिल रहा। टिकट रिफंड का मुद्दा दिसंबर 2025 में इंडिगो की उड़ानों में बाधा के दौरान भी सामने आया था, जब विमानन मंत्रालय ने एयरलाइन को निर्देश दिया था कि रिफंड को तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए। संशोधित नियम 24 फरवरी को जारी किया गया।

एयरलाइन को प्रदान करना होगा 'लुक-इन' विकल्प

अब एयरलाइन को यात्रियों को टिकट बुकिंग के 48 घंटे के लिए 'लुक-इन' विकल्प प्रदान करना होगा। इस अवधि में यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या संशोधित कर सकता है, बस संशोधित उड़ान के लिए सामान्य प्रचलित किराए का भुगतान करना होगा।

न्यूज़ ब्रीफ

मिलावटी दूध से पांच मौतों के बाद कार्रवाई तेज

अमरावती। आंध्र प्रदेश सरकार ने पूर्वी गोदावरी जिले में मिलावटी दूध से पांच लोगों की मौत के बाद राज्य में निगरानी और कार्रवाई के उपाय बढ़ा दिए हैं। गुरुवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार, राजमहेंद्रवरम में पांच मौतों और लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की रिपोर्ट के बाद यह सरकार ने यह कदम उठाया है। शुरुआती जांच से पता चला है कि रिपोर्ट किए गए मामलों में दूध का सेवन ही संक्रमण का संभावित कारण हो सकता है। राज्य सरकार ने दूध की बिक्री और स्टोरेज सेंटर्स पर जांच शुरू कर दी है और लैब टेस्टिंग के लिए पूरे राज्य से लगभग 150 नमूने एकत्र किए हैं।

यूएई से वांछित अपराधी भारत प्रत्यर्पित, हैदराबाद से गिरफ्तार

नई दिल्ली। इंटरपोल के रेड नोटिस पर वांछित एक आरोपी को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से भारत प्रत्यर्पित किया गया है। इस विशेष अभियान को सीबीआई के समन्वय से अंजाम दिया गया। दुबई पुलिस आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला को लेकर गुरुवार को राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर पहुंची। जहां से आंध्र प्रदेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने बयान जारी कर बताया कि आंध्र प्रदेश पुलिस के अनुरोध पर केंद्रीय एजेंसी ने आरोपी के खिलाफ पांच सितंबर 2022 को इंटरपोल के माध्यम से रेड नोटिस जारी करवाया था।

स्वयंभू बाबा के खिलाफ पॉक्सो के तहत केस दर्ज

यादगिर। कर्नाटक के यादगिर में एक वीडियो के वायरल होने के बाद एक स्वयंभू बाबा के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। वायरल वीडियो में कथित तौर पर 26 वर्षीय स्वयंभू बाबा सात वर्षीय बच्ची को गलत तरीके से छूते हुए दिख रहा है, जिससे लोगों में अक्रोश फैल गया। पुलिस ने बताया कि कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए मल्लिकार्जुन मुथ्या नाम के स्वयंभू बाबा के खिलाफ मामला दर्ज किया। आयोग ने यादगिर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर की रिपोर्ट मांगी है। वीडियो में आरोपी बच्ची को गोद में लिए हुए है और उसके माता-पिता की उपस्थिति में गलत तरीके से छूते और चूमते हुए दिखाई दे रहा है। मामले में पुलिस ने बच्ची के माता-पिता के बयान दर्ज किए हैं और मुथ्या को नोटिस जारी किया गया।

भूस्खलन पीड़ितों के लिए राहुल ने 100 घरों की रखी रखी नींव

तिरुवनंतपुरम। केरल के वायनाड में 2024 की भूस्खलन त्रासदी से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को 100 मकानों के निर्माण की आधारशिला रखी। यह पहल उन लोगों के लिए शुरू की गई है जिन्होंने प्राकृतिक आपदा में अपने घर, जमीन और परिजनों तक को खो दिया था। कार्यक्रम के जरिए पीड़ितों को भरोसा दिलाया गया कि पुनर्निर्माण की लड़ाई में उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। राहुल गांधी ने मुंडक्कई और चूरलमाला इलाके के भूस्खलन प्रभावित परिवारों से मुलाकात करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं है बल्कि लंबे समय तक साथ निभाने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि वायनाड उनके लिए परिवार जैसा है और जरूरत पड़ने पर कांग्रेस लगातार लोगों के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने माना कि मकानों के निर्माण में जमीन, अनुमति और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़ी कई जटिलताएं थीं, लेकिन अब उम्मीद है कि परियोजना तेजी से पूरी होगी।

पीड़ित परिवारों को मिलेंगे सुरक्षित और स्थायी घर

कांग्रेस की ओर से बनाए जा रहे 100 मकानों में हर घर करीब 1100 वर्ग फुट का होगा और प्रत्येक परिवार को लगभग 8 सेंट जमीन दी जाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य सिर्फ छत देना नहीं बल्कि लोगों को सम्मान के साथ नई शुरुआत का मौका देना है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में दो बड़ी भूस्खलन घटनाएं देखी हैं और हर बार लोगों ने कठिन हालात में भी साहस और एकजुटता दिखाई। उन्होंने पीड़ितों से कहा कि उन्होंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन उनका हौसला और इंसानियत अब भी मजबूत है।

प्रियंका गांधी ने उठाई पुनर्वास में देरी की बात

कार्यक्रम में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उन्होंने भूस्खलन के बाद लोगों की पीड़ा को करीब से महसूस किया है। कई परिवार पूरी तरह टूट गए और खेती तथा आजीविका खत्म हो गई। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सांसदों ने संसद में बार-बार वायनाड के लोगों की आवाज उठाई। गृह मंत्री से मुलाकात कर इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई। प्रधानमंत्री को पत्र लिखे गए और संसद के बाहर प्रदर्शन भी किए गए ताकि राहत और पुनर्वास प्रक्रिया तेज हो सके।

दादरा एवं नगर हवेली में बंद को मिला कांग्रेस का समर्थन

सिलवासा। सिलवासा में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर आयोजित बंद को दादरा एवं नगर हवेली प्रदेश कांग्रेस समिति ने समर्थन देते हुए इसे सफल बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रभु टोकिया ने सामाजिक मंच द्वारा 21 फरवरी को किए गए स्वैच्छिक और शांतिपूर्ण बंद के आह्वान का समर्थन किया। स्थानीय समाज एकता मंच के संयोजन में प्रभु टोकिया और दिगेश जोशी के नेतृत्व में आयोजित इस बंद में व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखीं। कांग्रेस ने इसे सामाजिक जिम्मेदारी और एकजुटता का प्रतीक बताया तथा व्यापारियों का आभार व्यक्त किया।

प्रेस नोट में हाल के दिनों में क्षेत्र में महिलाओं से जुड़े गंभीर अपराधों का हवाला देते हुए चिंता जताई गई। प्रेस सूचना ब्यूरो और गृह मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर बताया गया कि क्षेत्र में दुष्कर्म सहित कई गंभीर मामले दर्ज हुए हैं। कांग्रेस ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। पार्टी ने आरोप लगाया कि कुछ जनप्रतिनिधि इस विषय को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही स्पष्ट किया गया कि दर्ज एफआईआर कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और कानून अपना काम करेगा। कांग्रेस ने भरोसा दिलाया कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और न्याय सुनिश्चित करने के लिए वह लगातार आवाज उठाती रहेगी।

ट्रैफिक नियम बार-बार तोड़े तो रद्द हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस

एजेंसी । नई दिल्ली

अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस किसी स्कूल के रिपोर्ट कार्ड जैसा होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कर दिया है कि सरकार 'ग्रेडेड ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली' लाने जा रही है। इसका मतलब है कि हर ड्राइवर के खाते में कुछ पॉइंट्स होंगे, और जैसे ही आप कोई नियम तोड़ेंगे (जैसे रेड लाइट जंप करना या हेलमेट न पहनना), आपके 'खाते' से अंक कम कर दिए जाएंगे। यह सिस्टम केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि सबक सिखाने के लिए है। अगर ट्रैफिक नियम तोड़ते-तोड़ते आपके सारे पॉइंट्स खत्म हो गए, तो आपका लाइसेंस 6 महीने के लिए 'ठंडे बस्ते' में चला जाएगा (निलंबित)। और अगर आप फिर भी नहीं सुधरे और दोबारा 'कांड' किया, तो सरकार आपका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर देगी।

मौत के आंकड़ों ने बढ़ाई टेंशन

सड़क सुरक्षा सम्मेलन में गडकरी ने जो आंकड़े पेश किए, वे रोंगटे खड़े करने वाले हैं। भारत में हर साल 1.8 लाख लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं। इनमें से 72 प्रतिशत लोग 18 से 45 साल के हैं। मोबाइल पर कान सटाकर गाड़ी चलाना, शराब के नशे में झूमना और गलत साइड में गाड़ी घुसाना—ये वो गलतियां हैं जो हज़ारों घरों के चिराग बुझा रही हैं।

पीड़ितों के लिए 'मुफ्त मरहम' का कवच

सरकार ने सख्ती के साथ-साथ राहत का हाथ भी बढ़ाया है। अब एक्सीडेंट के बाद इलाज के खर्चे की 'चिक-चिक' नहीं होगी। 'पीएम राहत योजना' के तहत दुर्घटना के बाद पहले 7 दिनों तक किसी भी घायल को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस (Free) इलाज मिलेगा। यह सुविधा देश की किसी भी सड़क पर हुए हादसे के लिए लागू होगी।

सिक्किम में भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत

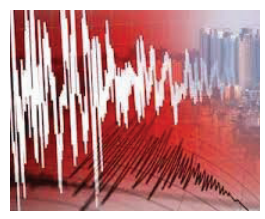

गंगटोक। सिक्किम में गुरुवार को भूकंप के 4.6 और 3.5 तीव्रता वाले झटके महसूस किए गए। अधिकारियों ने बताया कि पूर्वाह्न 11 बजकर 24 मिनट पर 4.6 की तीव्रता वाला पहला भूकंप आया। इसके बाद मांगन जिले में दोपहर 12 बजकर 17 मिनट पर 3.5 तीव्रता वाला भूकंप का दूसरा झटका महसूस किया गया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, पहले आए भूकंप का केंद्र ग्यालशिंग जिले के युक्सोम से चार किमी उत्तर-पूर्व में 10 किलोमीटर की गहराई में था। वहीं दूसरी बार का केंद्र गंगटोक से 11 किमी उत्तर-पश्चिम में 10 किमी की गहराई पर था। अधिकारियों ने बताया कि दोनों भूकंप में जानमाल के नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं है।

पुणे पोर्श हादसा

मुख्य आरोपी के पिता की जमानत याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस

मुंबई/नई दिल्ली। नई दिल्ली में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के पुणे पोर्श हादसे से जुड़े मामले में नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल की जमानत याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब किया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने इस अपील पर राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 10 मार्च तय की है। विशाल अग्रवाल ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 16 दिसंबर 2025 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। इससे पहले 2 फरवरी को शीर्ष अदालत ने इस मामले में तीन अन्य आरोपियों को जमानत दी थी और टिप्पणी की थी कि नाबालिगों से जुड़ी घटनाओं में अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बनती है।

19 मई 2024 का पुणे पोर्श हादसा

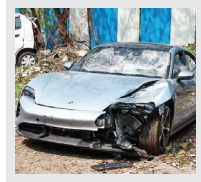

यह मामला 19 मई 2024 को पुणे के कल्याणी नगर इलाके में हुए भीषण सड़क हादसे से जुड़ा है। आरोप है कि 17 वर्षीय किशोर ने कथित तौर पर शराब के नशे में पोर्श कार चलाते हुए दो आईटी प्रोफेशनल्स को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इस घटना ने देशभर में आक्रोश पैदा किया था और नाबालिगों की जवाबदेही पर बहस छेड़ दी थी।

शिकंजे में 'फाल्कन घोटाले' का खिलाड़ी

792 करोड़ के घोटाले का है मामला

7,000 से ज्यादा शिकार और देशभर में 10 केस

हैदराबाद। तेलंगाना की अपराध अन्वेषण विभाग (CID) ने एक बड़े एक्शन में 'फाल्कन ग्रुप' के पूर्व चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) विकास कुमार सखारे को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। सीआईडी की एडिशनल डीजी चारू सिन्हा के मुताबिक, सखारे ने इस पूरे घोटाले में 'सक्रिय विलेन' की भूमिका निभाई। बुधवार को हुई इस गिरफ्तारी ने निवेश के नाम पर खेल करने वाले सिंडिकेट में हड़कंप मचा दिया है।

ऐप बनाकर बिछाया लालच का जाल

ठगी का तरीका बिल्कुल फिल्मी था। आरोपियों ने 'फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग' नाम का एक मोबाइल ऐप तैयार किया। इसके जरिए लोगों को झांसा दिया गया कि वे यहाँ पैसा निवेश करें और मोटा मुनाफा कमाएं। इसी ऐप की आड़ में 'कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड' जैसी कंपनियों ने करीब 7,056 लोगों से 4,215 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि इकट्ठा कर ली। जांच में सामने आया है कि कुल जमा रकम में से अकेले फाल्कन ऐप से जुड़ी कंपनी ने 4,065 लोगों के साथ 792 करोड़ रुपये की सीधी चपत लगाई है।

काम की खबर

UIDAI ने गूगल के साथ मिलाया हाथ

आधार सेंटर पर एक क्लिक पर पहुंचाएगा गूगल मैप

एजेंसी । नई दिल्ली

आधार कार्ड बनवाने या अपडेट कराने के लिए लोगों को अक्सर सही केंद्र खोजने में दिक्कत होती है। कई बार वे बंद हो चुके पुराने सेंटरों तक पहुंच जाते हैं, जिससे समय और मेहनत दोनों खराब होते हैं। इस समस्या को खत्म करने के लिए UIDAI ने गूगल के साथ साझेदारी की है, ताकि आधार सेवा केंद्रों की सटीक जानकारी सीधे गूगल मैप पर उपलब्ध हो सके। अब आधार से जुड़ा कोई भी काम कराने के लिए लोगों को सिर्फ गूगल मैप पर सर्च करना होगा। सर्च करते ही उनके आसपास मौजूद अधिकृत आधार सेवा केंद्रों की जानकारी सामने आ जाएगी। इससे भटकने की परेशानी खत्म होगी और सही स्थान तक पहुंचना आसान होगा।

दिव्यांग सुविधा और समय की जानकारी

यूजर्स को यह भी पता चल सकेगा कि संबंधित आधार केंद्र दिव्यांग फ्रेंडली है या नहीं, पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है या नहीं, केंद्र के खुलने और बंद होने का समय क्या है और किन दिनों में अवकाश रहता है।

60 हजार केंद्रों तक आसान पहुंच

UIDAI के मुताबिक देशभर में करीब 60 हजार आधार सेवा केंद्र संचालित हैं। गलत या अधूरी जानकारी के कारण लोगों को कई बार परेशानी झेलनी पड़ती है। अब आधिकारिक डेटा के साथ सभी केंद्रों की सही जानकारी उपलब्ध होने से यह समस्या काफी हद तक दूर होगी। गूगल मैप पर केवल अधिकृत और वैध आधार सेवा केंद्र ही दिखाई देंगे।

जल्द लॉन्च होगा नया फीचर

आईटी मंत्रालय के अनुसार अगले कुछ महीनों में गूगल मैप पर यह सुविधा शुरू हो जाएगी। यह फीचर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, ताकि देशभर के नागरिक इसका लाभ उठा सकें।

सेवाओं की पूरी जानकारी भी मिलेगी

गूगल मैप पर सिर्फ केंद्र का पता ही नहीं, बल्कि यह भी बताया जाएगा कि वहां वयस्कों का नामांकन होता है या नहीं, बच्चों का आधार बनता है या केवल अपडेट की सुविधा उपलब्ध है। इससे लोगों को पहले से ही स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी।